● वर्ष-2
● अंक-242
रायपुर, गरुवार
01 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

कांग्रेस 85% कमीशन खाने वाली पार्टी-मोदी

रिमोट कंट्रोल से चल रही थी कांग्रेस सरकार, सीमा पर सड़क बनाने से डरती थी

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाजपा का चुनावी महासम्पर्क अभियान शुरू करते हुए जनसभा में कहा- कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85 परसेंट कमीशन खाने वाली पार्टी है। मोदी ने कहा- बीजेपी सरकार ने पिछले 9 सालों में आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार हम विचार करें, तो 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लुट जाते। ना रेलें बनती, ना हाईवे बनते। बीते सालों में केंद्र सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से डायरेक्ट गरीबों के खाते में डाले। अगर कांग्रेस सरकार होती तो 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लुट जाते। पीएम ने कहा जब लूट की बात होती है ना, तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। गरीब, दलित पीड़ित, शोषित, अल्पंख्यक, दिव्यांग, महिला, सबको समान भाव से लूटती है।

मोदी ने कहा- आजकल बहुत से लोग पूछते हैं, देश में जो बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। उसके लिए मोदी ये पैसा लाता कहां से है। चारों और विकास के काम चल रहे हैं मोदी पैसा लाता कहां से है? मैं बताता हूं पहले पैसे कहां जाते थे और अब कहां जाते हैं। हमारे देश में विकास के कामों के लिए पैसों की कमी कभी नहीं रही। यह जरूरी है कि जो पैसा सरकार भेजे, वो पूरा पैसा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी, जो देश के विकास को खाए जा रही थी और खोखला कर रही थी। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने माना था केंद्र सरकार जो 100 पैसे भेजती है, उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85 परसेंट कमीशन

खाने वाली पार्टी है।

कांग्रेस पर निशाना

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी? पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। बड़े-बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपरपावर थी, कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। लेकिन आपने 2014 में अपने एक वोट से सब कुछ बदल दिया। पूरी दुनिया अब भारत के विकास की बात कर रही है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है- गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है।

मोदी ने कहा कि आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। ये कांग्रेस ही है जो वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। भाजपा सरकार ने ना सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में, भाजपा सरकार ने 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन दिए हैं। इस संख्या को पूरा करने में कांग्रेस सरकार को 20 साल लग जाते। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे, वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी, जो देश के विकास को खाए जा रही थी।

कर्नाटक में भाजपा की हार के बावजूद मोदी सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा

जेफरीज का कहना है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार और दिसंबर 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावों की चुनौतियों के बावजूद मई 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। जेफरीज के क्रिस वुड ने अपने ग्रीड एंड फियर नोट में कहा कि 10 मई को कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हालिया जीत के बावजूद, प्रचलित धारणा यह है कि मोदी और भाजपा सरकार आगामी चुनावों में फिर से चुने जाएंगे, हालांकि संभावित रूप से कम बहुमत के साथ। 2019 में हुए पिछले आम चुनावों में, भाजपा ने लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 303 पर जीत हासिल की थी। इस बार, जानकारों का अनुमान है कि भाजपा लगभग 270 सीटें हासिल कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक की तरह राज्य के चुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कर्नाटक में सत्ताधारी दल ने 1985 के बाद से दोबार जीत दर्ज नहीं की है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय चुनाव व्यापक चिंताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं और मोदी के कार्यकाल के दौरान परिवर्तनकारी परिवर्तनों को व्यापक रूप से लोगों ने मान्यता दी है। वुड ने अपने ग्रीड एंड फियर न्यूजलेटर में भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जोर दिए जाने की प्रशंसा की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राष्ट्रीय चुनावों में वोटर महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। सत्ता में अपने 10 वर्षों के दौरान मोदी की उल्लेखनीय उपलब्धियों से सकारात्मक छवि बनी है।

इन दिनों

✍ जितेंद्र भारद्वाज

पहलवानों का आंदोलन हुआ हाईजैक

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे पहलवानों की लड़ाई जंतर-मंतर से गंगा (हरिद्वार) तक पहुंच गई। किसान नेता नरेश टिकैत ने गंगा में मेडल बहाने से पहलवानों को रोक दिया। अब आगे क्या करना है, ये सब पांच दिन में तय होगा। जंतर मंतर पर कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी था, दिल्ली पुलिस किसी को वहां आने-जाने से रोक नहीं रही थी। इस आंदोलन में शामिल लोगों के बीच मनभेद भी हुआ और मतभेद भी रहा। जाट बनाम ठाकुर हुआ तो वहीं राजनीतिक दलों द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास भी हुआ। 28 मई को नए संसद भवन के बाहर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर वहां मौजूद लोगों में जबरदस्त मतभेद रहा। इस बाबत दो समूह बन गए। एक का कहना था कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक एतिहासिक दिन है, इसमें बाधा डालना ठीक नहीं है। इसके बावजूद पहलवानों ने संसद भवन की ओर जाने का प्रयास किया। पहलवानों के आंदोलन के दो चरण रहे हैं। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ था। उस वक्त पहलवानों ने राजनीतिक दलों को अपने मंच पर नहीं आने दिया। पहलवान बबीता फोगाट, जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कही। तभी बृजभूषण शरण सिंह खेमे की ओर से कहा गया कि ये आंदोलन हरियाणा के एक अखाड़े और एक परिवार का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को उकसाने का आरोप लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाट बनाम ठाकुर की पोस्टों की भरमार हो गई। पहलवानों के आंदोलन को एक जाति से जोड़ने का प्रयास किया गया। बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवान, जंतर मंतर से उठ गए। जब तीन माह तक कुछ नहीं हुआ, तो वे दोबारा से यहां पहुंच गए। इस बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों, किसान नेताओं, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों से आग्रह किया कि वे उनका साथ दें। इसके बाद प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पूर्व सीएम ओपी चौटाला और दूसरे कई नेता पहलवानों को अपना समर्थन देने पहुंच गए। दूसरे चरण के शुरू में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया। मामला दर्ज हो गया और पहलवानों के बयान भी हो गए। बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी। अब पहलवानों ने कहा, पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करे। अब यह आंदोलन पूरी तरह से दो जातियों के बीच बंट चुका था। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पहलवानों को एक जाति विशेष से जोड़कर देखा गया। इस वजह से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर आए। कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं दलित नेता उदित राज भी नियमित तौर पर पहलवानों के आंदोलन में पहुंचते रहे। राजस्थान से गुर्जर समुदाय को साथ लाने की कोशिश हुई। बतौर पुष्पेंद्र सिंह, इस आंदोलन की दिशा को भटकाने का प्रयास हुआ है। आंदोलन को जाति विशेष से जोड़ दिया गया। गुरुवार को सोरम (मुजफ्फरनगर) में खाप पंचायत होगी। उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। पहलवान भी खाप पंचायत में मौजूद रहेंगे।

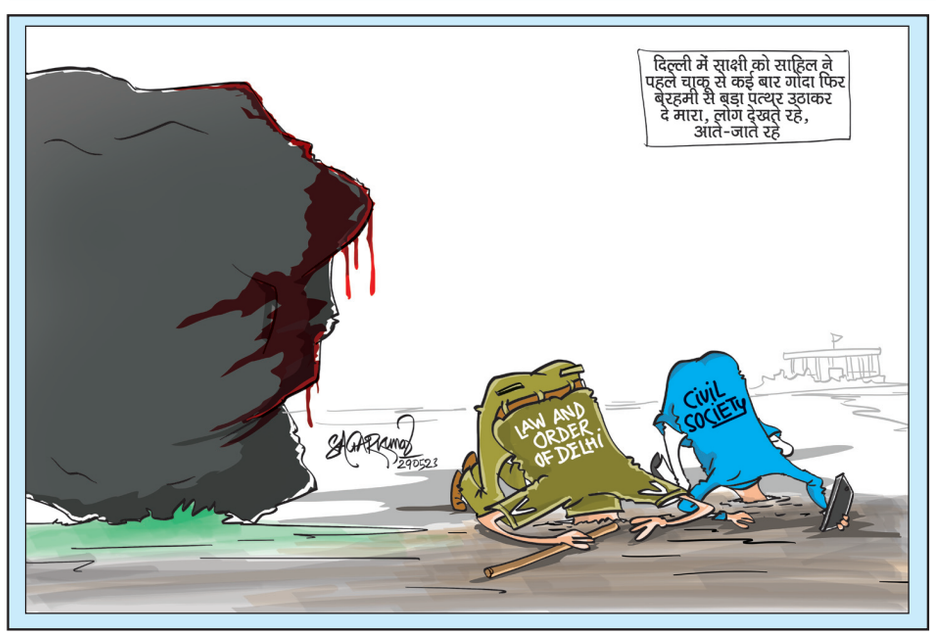

रायगढ़ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला

रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर आवास मेडिकल कॉलेज के पास किराये मकान में रहने वाली युवती की सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 8 मार्च को इलाज दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी ।

थाना सरकण्डा, बिलासपुर से मर्ग डायरी अग्रिम जांच के लिये थाना चक्रधरनगर को प्राप्त हुई । जांच में मृतका के परिजनों से कथन लेकर जांच की गई। इसमें परिजनों ने बताया कि युवती को अविवाहित बताकर उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाले दानिश खान उर्फ समीर हसन पिता जमाल खान उम्र 27 वर्ष निवासी इंदिरा नगर रायगढ़ थाना कोतवाली ने युवती को गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीके से दवाई खिला दी थी। इससे युवती

की तबीयत बिगड़ी और इलाज दौरान उसकी मौत हुई है ।

मर्ग जांच में आरोपी दानिश खान उर्फ समीर हसन पर थाना चक्रधरनगर में 29 मई को गैर इरादतन हत्या (धारा 304 आईपीसी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया । मामला संवेदनशील होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय द्वारा मामले की डायरी को अपने हस्ते लिया गया ।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी सीएसपी रायगढ़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उपनिरीक्षक जीपी बंजारे एवं हमराह स्टाफ द्वारा कल आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जांच में मृतका के कॉल रिकॉर्ड व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की जब्ती कर विधिवत गिरफ्तारी करते हुए रिमांड पर भेजा गया। आरोपित का जेल वारंट जारी होने पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया है ।मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसे गंभीर बताया है और महामंत्री पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ की घटना को लव जिहाद बताया है। उन्होंने अपने वीडियो सन्देश में प्रदेश के लोगों से कहा है कि लोगो ने लव जेहाद की केरल स्टोरी देखी ,अब लव जेहाद की छत्तीसगढ़ की स्टोरी से रूह काप रही है। पीड़ित परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा हैं।

प्रमुख समाचार

बेहतर रही रफ्तार, जीडीपी की ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत के पार

नईदिल्ली। देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही है। भारत सरकार के अनुसार 2022-23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

2021-22 में 9.1 प्रतिशत की तुलना में 7.2 प्रतिशत अनुमानित है। केंद्रीय सांख्यकीय मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4 फीसदी दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी दर 4.4 फीसदी थी। जबकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में ये 6.3 फीसदी थी और वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में ये 13.2 फीसदी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले संकेत दिए थे कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर में तेजी जारी रहेगी।

राहुल की मोहब्बत की दुकान में खालिस्तानियों ने डाला व्यवधान

नईदिल्ली। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को अमेरिकी राय कैलिफोर्निया में एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने घेर लिया था। गांधी 10 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिसको में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम को संबोधित किया। एक वीडियो में खालिस्तान समर्थकों को राहुल गांधी को परेशान करते और सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम को बाधित करते हुए दिखाया गया है। कार्यक्रम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जब दर्शकों में से कुछ लोगों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में उनके और गांधी परिवार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ देर के लिए उनके भाषण को बीच में ही रोक दिया। हालाँकि, गांधी मुस्कुराए और कहा कि स्वागत है, स्वागत है ... नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। इसके बाद कांग्रेस नेता दर्शकों में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए और भारत जोड़ो के नारों के साथ जवाब दिया।

अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा अहमदनगर

नईदिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को घोषणा की कि राय के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा। यह घोषणा प्रारंभिक-आधुनिक भारत में मराठा साम्राय की वंशानुगत महारानी अहिल्या बाई होल्कर की जयंती पर की गई है। राय सरकार ने घोषणा की कि अहिल्या बाई होल्कर का सम्मान करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार उनके नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदल देगी। महाराष्ट्र के सीएम ने चौंधी, नगर जिले में घोषणा की, जहां उन्होंने अहिल्या बाई होल्कर की जयंती मनाई। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सीएम शिंदे और कई राय मंत्री अहमदनगर में मराठा मालवा साम्राय की होल्कर रानी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित थे, जिन्हें पूरे भारत में मंदिरों और धर्मशालाओं (सार्वजनिक विश्राम गृह) के निर्माण के लिए जाना जाता है।

ज्ञानवापी मामले में खारिज की मस्जिद समिति की याचिका

नईदिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 12 सितंबर, 2022 को वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल दायर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की याचिका को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दायर हिंदू उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। पिछले साल दिसंबर में जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि मस्जिद समिति ने अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके कुछ दिनों बाद वाराणसी कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

आरोप साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा: बृजभूषण

नईदिल्ली। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर उत्पीड़न का भी

आरोप लगाया है। हालांकि, ताजा खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विरोध करने वाले पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत अब तक नहीं दे सके हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो उसे पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा में मेडल बहाने से फांसी नहीं हो जाती। ये सब इमोशलन ड्रामे हैं। बाराबंकी में उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं।

मणिपुर हिंसा

पूर्वोत्तर प्रदेशों में हिंसा के पीछे परदेसी हाथ?

राजेश बादल

मणिपुर जल रहा है आमतौर पर शांत रहने वाले इस खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश के नागरिक इस दावानल से दुखी हैं। ऐसी हिंसा उन्होंने 74 साल में कभी नहीं देखी राजधानी इंफाल में अत्याधुनिक विदेशी हथियारों से लैस सैकड़ों उग्रवादी घुसे हुए हैं। उनमें से चालीस मारे गए हैं। सौ से अधिक निर्दोष नागरिक जान गंवा चुके हैं। सतही तौर पर भले ही यह मैतेई और नगा-कुकी के बीच विवाद नजर आता हो, लेकिन परदे के पीछे की कहानी कुछ हिंदुस्तान की भौगोलिक और सांस्कृतिक-सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हैं तो पाते हैं कि इस मुल्क के सूबों में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ घटती हैं कि सब पर नजर रखना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है।

पूर्वोत्तर प्रदेशों को भले ही सेवन सिस्टर्स के नाम से हम जाने-पहचानें, मगर यह भी सच है कि अरसे तक मिजोरम में इसी तरह की हिंसा और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपती रही हैं। असम भी इसी तरह आंतरिक अशांति और खून-खराबे का शिकार रहा है। गोरखालैंड की मांग और दार्जीलिंग के इर्दगिर्द स्थानीय पृथकतावादी समूह पनाह पाते रहे हैं। पहली बार राजीव गांधी की सरकार ने इन मसलों पर गहराई से विचार किया था। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा ने

राजीव गांधी सरकार के साथ जब जून 1986 में समझौता किया तो वहां शांति के नए दरवाजे खुले. मिजो नेशनल फ्रंट ने हथियार डाले और लोकतांत्रिक मुख्य धारा में शामिल हो गया। लालडेंगा मुख्यमंत्री बने यह तो केवल दो उदाहरण हैं। कहा जा सकता है कि जब-जब भी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया तो अपनी पहचान के साथ शामिल हुए। जहां तक मणिपुर के ताजा दौर की बात है, उसमें प्राथमिक तौर पर प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी दिखाई देती है। लगातार अपनी-अपनी पहचान के साथ रहती आ रही मैतेई और नगा-कुकी कभी आपस में खून खराबे के इस हालात तक नहीं पहुंचे।

नगालैंड और मणिपुर के बीच यदाकदा मतभेद पनपे भी तो उन्हें समझदारीपूर्वक सुलझा लिया गया लेकिन इस बार धीरे -धीरे परिस्थितियां गंभीर रूप लेती रहीं और स्थानीय सरकार तथा प्रशासन उसके विवेकपूर्ण हल खोजने की दिशा में काम नहीं कर पाया। यह बेतुकी बात थी कि सरकार ने वहां वनभूमि में निवास कर रहे नगा और कुकी जनजाति के लोगों को घुसपैठिया बताते हुए उन्हें बाहर खदेड़ने का निर्णय लिया। चूराचांदपुर के यह नगा-कुकी इससे खफा थे। उनमें अधिकतर ईसाई धर्मावलंबी हैं। भारतीय मतदाताओं को अपने ही मुल्क में घुसपैठिया बताने का यह अजीबोगरीब उदाहरण है। मैतेई वहां बहुसंख्यक हैं और जब हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया तो इसी श्रेणी के नगा-कुकी भयभीत हैं कि अब उनके अधिकारों में कटौती हो जाएगी। इस अदालती आदेश ने आग में घी डालने का काम किया। राज्य सरकार ने यहां संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुकी समुदाय के अनेक संगठन उग्रवादी समूहों में बंटे रहे हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में उनके साथ संधि की और उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई रोक दी इसके बाद सब शांत चल रहा था पर राज्य सरकार ने इसी बरस 10 मार्च को दो संगठनों के साथ इकतरफा समझौता तोड़ने की घोषणा कर दी। जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी नाम के यह दोनों हथियारबंद संगठन हैं। इस तरह पहले से जारी तनाव ने एक और घातक शक्ल अख्तियार कर ली महत्वपूर्ण यह है कि पूर्वोत्तर के अधिकतर हथियारबंद संगठनों के तार भारत से बाहर भी जुड़ते हैं। चीन और म्यांमार के मधुर संबंध इन दिनों इन सशस्त्र संगठनों के लिए बड़े काम के साबित हुए हैं। उन्हें म्यांमार के रास्ते हथियार मिलते रहे हैं और सैनिक प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण भी मिलता रहा है। नौ साल पहले म्यांमार में चल रहे ऐसे ही कुछ शिविरों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की थी। उसके बाद वाहवाही भी लूटी गई जाहिर है इससे म्यांमार ने अपमानित महसूस किया। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की मुखिया आंग सान सू ची जेल में बंद हैं और चीन सरकार वहां की फौजी हुकूमत को भारत के विरुद्ध जब तब उकसाती रहती है। हिंदुस्तान को ध्यान में रखना होगा कि जो समस्या देखने में घरेलू दिखाई देती है, उसके तार दूर कहीं किन्हीं ताकतों के हाथ में होते हैं।

नक्सलियों ने 150 बोरी तेंदूपत्ता को आग के हवाले किया

कांकेर। बडग़ांव थाना अंतर्गत दो अलग-अलग जगहों पर नक्सलियों ने तेंदूपत्ता फड़ में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली आगजनी से 150 बोरी में भरे तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गई है। चौकाने वाली बात यह है कि बडग़ांव थाना से मात्र सौ मीटर की दूरी पर रात्रि करीबन 12 बजे नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

गौरतलब है कि अब तक क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक तेंदूपत्ता फड़ में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने तेंदूपत्ता का सैकड़ा छह सौ रुपये नही करने वाले ठेकेदार को मार भागने का फरमान भी जारी किया है। यह सर्व विदित है कि नक्सलियों के बड़े आर्थिक स्त्रोंतों में से एक तेंदूपत्ता की लेव्ही वसूली से मिलता है, लेकिन इस वर्ष बेमौसम बारिश से बहुत ही कम मात्रा में तेंदूपत्ता की खरीदी होने से एवं तेंदूपत्ता की मांग बाजार में भी कम होने से नक्सलियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। जिससे बौखलाये नक्सली जिस इलाके से लेव्ही नही मिला उन इलाकों में आगजनी की वारदात को अंजाम देकर वसूली के लिए दबाव बनाने में लगे हुए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बडग़ांव थाना के पास स्थित तेंदूपत्ता फड़ में आठ से दस हथियार बन्द नक्सली रात्रि करीबन 12 बजे यहां पहुंचे और वहां काम करने वाले सभी मजदूरों को उठाया और तेंदूपत्ता को आग के हवाले कर लाल सलाम जिंदाबाद के नारा लगाते हुए फरार हो गये। इसके अलावा ग्राम मासुर में रखे तेंदूपत्ता को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है, जिससे लगभग 50 बोरे में रखे तेंदूपत्ता जलकर खाक हो गया है। नक्सली आगजनी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद बडग़ांव थाना प्रभारी लक्ष्मण केंवट जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है।

नक्सलियों के दण्डकारण्य महिला संगठन ने महिला पहलवानों के आंदोलन का किया समर्थन

जगदलपुर। नक्सलियों के दण्डकारण्य क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन के प्रवक्ता रामको हिचामी ने प्रेस नोट जारी कर महिला पहलवानों पर हुए दमनकारी कार्यवाही की निंदा की है। तिरंगे को झुकने नहीं देने की पहलवानों के प्रयास को बल पूर्वक नाकाम करने का उल्लेख करते हुए नक्सल प्रवक्ता ने महिला पहलवानों को आंदोलन जारी रखने का आह्वान करते हुए महिला पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने की बात नक्सलियों ने प्रेस नोट में कही है। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के लिए जिम्मेदार भाजपा सांसद व कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है।

2000 हजार के नोट की वापसी का नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी कर किया विरोध

जगदलपुर। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने जारी विज्ञप्ति में 2000 हजार रूपये के नोट की वापसी के फैसले का विरोध करते हुए इसके विरूद्ध जनांदोलन का आह्वान किया है। उन्होने कहा कि हिंदुत्व फासीवादियों ने देश की अर्थ व्यवस्था को डिजिटल अर्थ व्यवस्था में बदलने के काम पर लगे है। खासकर अमिरिकी डिजिटल लेन-देन चलाने वाले कंपनियां और उनके संपर्क में रहे रिलायंस, अदानी, टाटा, वगैरह कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 2000 हजार रूपये के नोट बंदी हुई है। नक्सली प्रवक्ता समता ने एक बयान में कहा कि 2016 की नोट बंदी के समय में 106 लोग मारे गये थे तथा 1.40 लाख सूक्ष्म, छोटे और मंझोली कम्पनियां बंद हुई थी, 40 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए जिनका काम बंद हो गया, फिर भी काला धन का पता नहीं मिला था। उस समय नोट बंदी के कारण देश की अर्थ व्यवस्था को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। यह धन राशि फिर जनता से कर के रूप में वसूला गया था। आज देश का जीडीपी 250 लाख करोड़ है एवं 94 प्रतिशत आबादी असंगठित क्षेत्र में जीवन यापन कर रहे है। कुछ आर्थिक विश्लेषक बताते है कि 2000 रूपये नोट पूरे नगद में 10.48 प्रतिशत है, इसके रद्द करने से जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ यह गलत आंकलन है। 2000 हजार रूपये के नोट रद्द करने के चलते बैंकों में डिपॉजिट का पैसा बढ़ेगी बढ़े हुए पैसे को बैंको कार्पोरेट कंपनियों को ऋण देगा। इसके साथ-साथ ई-कामर्स कंपनियों का व्यापार जोर पकड़ेगा। सेवा कर के रूप में उन कंपनियों की आमदनी बढेगी। कंपनियों के फायदे के लिए नोट बंदी किया है। यह, 90 प्रतिशत जनता को नुकसान देने वाला है।

राजस्थानी सुलह फार्मूले को छत्तीसगढ़ में भी अपनाने की अटकले तेज

अंबिकापुर। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद आगामी चुनावों में गुटीय राजनीति और मतभेद को समाप्त कर मन मिले या नहीं मिले हाथ मिलाये रहिए फार्मूले को गंभीरता से अपनाने की दिशा में कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है, मतभेद की खाई जो अंदर तक पड़ चुकी है वहां सुलह समझौते कितना असरदायक होगे यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

फिलहाल राजस्थान में गहलोत एवं पायलट के बीच उत्पन्न गुटीय लड़ाई को समाप्त करने की दिशा में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पहुंचे राहुल गांधी एवं वरिष्ठ जनों ने किसी तरह पार्टी को एकजुट रखने की दिशा में निर्णय लिया है उनके इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी अटकलों की चर्चा गर्म है।

यहां पर मुख्यमंत्री पद के अढ़ाई अढ़ाई साल के दो वारिसों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने बीच में हटाना जरूरी नहीं समझा इस दिशा में शेष ढाई साल के मुख्यमंत्री पद के दावेदार टीएस सिंह देव सरगुजा महाराज की हर कोशिश नाकाम रही। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष में तरह-तरह की चर्चा से दोनों के बीच सामंजस्य नहीं होने और दूरियां बढ़ने के अनेकों उदाहरण जो सामने आए उससे यही लगा कि सिंहदेव के धैर्य की परीक्षा लेने और उनके मुखर विरोध पर खुलकर कुछ ना कह पाने को शायद आलाकमान उनकी कमजोरी समझ बैठा।

फिलहाल अगले चुनावों को लेकर प्रदेश में तैयारियां पार्टी के भीतर और बाहर तेजी से चल रही है ऐसे समय में पिछले 15-20 दिनों से उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर 13 जून को सिंहदेव के विदेश से रायपुर वापसी के बाद संभव है जय वीरू की जोड़ी के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच बढ़ती दूरियों को समाप्त करने की दिशा में राजस्थान फार्मूले की तरह एक प्रयास की खबर चर्चा में है वैसे श्री सिंहदेव ने अपनी तरफ से पहले ही कई अवसरों पर स्पष्ट करते हुए आलाकमान को आश्वस्त कर दिया है कि वे जीवन पर्यंत राजनीति में रहते हुए कांग्रेस से अलग नहीं होंगे वैसे भी राजनीति में सब कुछ जायज वाले फॉर्मुले में ऊंट कब और किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता जो कहा जाता है वह किया नहीं जाता वही फार्मूला राजनीति में चलते आया है।

और अंत में वर्तमान में सरगुजा के सभी 14 सीटों पर कांग्रेस काबिज़ है विपक्ष का खाता भी नहीं खुला इसमें मुख्यमंत्री के पद पर सिंहदेव की ताजपोशी तय मानी जा रही थी। यह भी एक कारण था। आगामी चुनाव में किसी भी स्थिति में सभी सीटें कांग्रेस के पाले में नहीं आ सकती। यदि सीटें कम हुई तो सिंहदेव को जवाबदार या भितरघात का आरोप भी लगाया जा सकता है यहां विपक्षी भाजपा 8 से 10 सीटों के लिए प्रयासरत है। जिले के कई मंत्री भी अब अपने विधानसभा की जगह नये स्थान के लिए अभी से जुगाड़ भिड़ाने में लगे हैं।

चुनाव लड़ने का सबको अधिकार, किसी को रोका नहीं जा सकता : ओम माथुर

कांकेर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। .ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने इसकी शुरुआत बस्तर संभाग से कर दी है। इसी के तहत भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के दौरे पर हैं। वह बुधवार को कांकेर पहुंचे और तीनों विधानसभा के सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओ से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति और कार्य करने के तरीकों की जानकारी देकर कार्यकर्ताओ में जोश भरा।

प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि, इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर आ रही है। अभी कार्यकर्ता जमीनीस्तर पर मजबूत हैं। कहा कि, सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और राज्य की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की हकीकत लोगों को बताएंगे। वहीं आदिवासी समाज के विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को नहीं रोका जा सकता, बाकी समय समय की बात है।

कवासी लखमा ने ली माथुर के बस्तर दौरे पर चुटकी

हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के लगातार बस्तर दौरे को लेकर फिर चुटकी ली है,किराये के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं लेकिन रमन-बृजमोहन को क्यों नहीं बिठा रहे हैं? इसलिए कि उन्हे अपने ही पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं हैं। वे तो कहते हैं कि बस्तर की 12 सीटों पर भाजपा आगामी चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पायेगी।

आदिवासियों से कांग्रेस ने आवास, रोजगार, संस्कृति सब कुछ छीन लिया है : कश्यप

जगदलपुर। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के बस्तर दौरे पर दिए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के कुशासन में हजारो बच्चों की मौत इलाज के अभाव में हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे आदिवासी थे। यह सीधे तौर पर हत्या जैसा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से सब कुछ छीनने के बाद उनके पास केवल उनकी संस्कृति ही बची थी, कांग्रेस उसे भी छीन रही है, आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, और जो लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस की तुगलकी सरकार जेल में ठूंस रही है। आदिवासी समाज अपने साथ हो रहे प्रत्येक अन्याय का जवाब कांग्रेस को देने के लिए तत्पर है। आज कांग्रेस के शासन में आदिवासी अंचल के इलाकों में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। इलाज के अभाव में छोटी-छोटी बीमारियों से लोगों की जान जा रही है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों का आवास छीना, घरों में नल नहीं लगने दिए, भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही सारी योजनाएं बंद कर दी गई, तेंदूपत्ता संग्राहक, बिना चप्पल पैदल चलकर अपना तेंदूपत्ता महाराष्ट्र ले जाकर बेचने को मजबूर हैं, कांग्रेस की सरकार ने उनका रोजगार भी छीन लिया है।

गौठान निरीक्षण करना छोड़ अपना अस्तित्व बचाने का कार्य करे भाजपा - लखेश्वर

जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष व बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक सुभाऊ कश्यप के गोठान में अनियमितता पर उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौठान का निरीक्षण करना छोड़ सबसे पहले अपना अस्तित्व बचाने का काम करे,भाजपा गौठान के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है। चुनाव नजदीक आ गया है, तब भारतीय जनता पार्टी गोठान का दौरा कर रही हैं, इससे पहले भाजपा ने गौठानो का निरीक्षण क्यों नही किया? लखेश्वर बघेल ने कहा कि आज प्रदेश में गायों के सरंक्षण का कार्य हो रहा है, जिसके कारण भाजपाइयों के पेट में दर्द उठ रहा है। विगत 15 वर्षों तक गौठान के नाम पर घोटाला भाजपा की सरकार ने किया है, दो दिन निरीक्षण कर 1300 करोड़ रूपये के गौठान निर्माण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे मुद्दाविहीन भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता खोने के कारण कुछ भी बयानबाजी कर रही है। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विकास कार्यों को देखकर बौखलाई भाजपा हर दिन तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, पर आम जनता सब समझ रही है। पशुधन सरंक्षण के लिए तैयार गौठान पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण है,आज छत्तीसगढ़ के मॉडल की देश-दुनिया में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विगत चार सालों में गरीबो, मजदूरों व किसानों हित में कार्य कर छत्तीसगढिया अस्मिता को जगाने का कार्य किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाजयुमो ने नियुक्त किए प्रभारी

कोरबा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के अनुमोदन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.राजीव सिंह की अनुसंशा से भाजयुमो जिलाध्यक्ष पंकज सोनी ने जिले के सभी 19 मंडलों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी पाली के युवा नेता दीपक शर्मा को चैतमा मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। दीपक शर्मा पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दें चुके हैं और क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। इनके अलावा कोरबा मंडल के लिए अनुराग राठौर, कोसाबाड़ी मंडल दिव्यांश अग्निहोत्री, बालको प्रेमचंद पाण्डेय, दर्री रंजू यादव, बांकीमोंगरा अनुप यादव, कटघोरा विवेक मारकण्डेय, हरदीबाजार वैभव शर्मा, भिलाईबाजार पंकज धुर्वा, दीपका नरेन्द्र देवांगन, पाली राधेश्याम सिंह, पोड़ी-उपरोड़ा अनुराग दुहलानी, चोटिया गंगा पटेल, पसान राजा डिक्सेना, करतला नीरज मिश्रा, उरगा प्रवीण उपाध्याय, कुदमुरा दिनेश तिवारी, बरपाली बृजेश यादव तथा गढ़-उपरोड़ा के प्रभारी रजत खूंटे नियुक्त किए गए हैं।

शराब घोटाला के विरोध में भाजयुमो का पोस्टर अभियान

कोरबा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल एवं भाजपा महिला मोर्चा मंडल हरदीबाजार ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ को लूटने वाली प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा दो हजार करोड़ रुपये का शराब घोटाला करने के विरोध में मंगलवार को कॉलेज चौक हरदीबाजार में पोस्टर अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष चुलेश्वर राठौर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ज्योति पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री पंकज धुरवा, भाजयुमो जिला कार्यसमिति सदस्य कृष्णानंद राठौर, भारतीय जनता महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष उषा विश्वकर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कृष्णा पटेल, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नवरत्न सिंह राजपूत, भाजपा सोशल मीडिया संयोजक बजरंग यादव, भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष आकाश राठौर, विनय चंद्राकर, महामंत्री नरेंद्र अहीर, भाजपा नेता राजेश राठौर, राजकुमारी यादव, शांति बाई यादव, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वेतन विसंगति को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा

नगरी। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निर्देशानुसार गुरुजी करे पुकार, वेतन दूर करो सरकार। अंतिम बार गुरुजी करे गुहार, विधायक के द्वार, कार्यक्रम के अंन्तर्गत 26 मई को सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव से सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक शाखा नगरी के संगठन के द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा विधायक महोदय को सविस्तार वेतन विसंगति के संबंध में जानकारी दिया गया,जिस पर विधायक ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से चर्चा करने एवं ज्ञापन को पहुंचाने की बात कही।आज ज्ञापन सौपने वालों में समग्र शिक्षक/सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष शरीफबेग मिर्जा,सचिव गजानंद सोन, संगठन मंत्री राजेंद्र टांडेश, अंकेक्षक अनिल कुमार साहू,सुरेन्द्र प्रजापति, दीपक कुमार साहू, योगेश्वरी ध्रुव, खीरभान नेताम,ओमप्रकाश बेतकार, संतोष बाधव, नीषित सोम,एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

जिपं सीईओ ने की गोधन न्याय योजना की समीक्षा

धमतरी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रोक्तिमा यादव ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आज गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, उद्यानिकी, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को समन्वित तरीके से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन तथा बिक्री की गहन समीक्षा करते हुए वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर श्रीमती यादव ने जिले में गोधन न्याय योजना के तहत की जा रही गोबर खरीदी के संबंध में जानकारी ली तथा लक्ष्य के अनुरूप गोबर की खरीदी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी, आयुक्त नगरपालिक निगम श्री विनय पोयाम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी डॉ. विभोर अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने की फौती नामांतरण व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग

कोरबा। कोरबा जिले के हरदीबाजार तहसील अंतर्गत गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फौती नामांतरण व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग की है। मामले की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे थे। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 राजनंदनी, ग्राम पंचायत पुटा सरपंच सुमरित बाई सहित ग्रामीणों ने कहा है कि वे ग्राम पंचायत पुटा के निवासी है। ग्राम पुटा में एसईसीएल करतली ईस्ट ओपन कास्ट परियोजना प्रस्तावित है। चूंकि उनके ग्राम में किसानों की अवस्थित कृषि भूमि एसईसीएल परियोजना से प्रभावित होने के कारण प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित किसानों की कृषि भूमि, वन भू-अधिकार पट्टा, खसरा, रकबा त्रुटि, किसानों का फौती नामांतरण व पूर्व में दर्ज किये गये बंटवारा फौती नामांतरण का राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती नहीं हुआ है। इसके कारण ग्रामवासियों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

गौठान समिति बनाकर सरकार प्रतिमाह भर रहे हैं कांग्रेसियों की झोली

■ गौरव ग्राम कंडेल के गौठान का डीपेंद्र साहू के साथ ग्रामीणों ने किया निरीक्षण

धमतरी। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता डीपेंद्र साहू एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू गौरव ग्राम कंडेल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर गौठान का निरीक्षण किए, जहां पर सभी ने कहा कि गौठान की स्थिति पूर्णतया: बदहाल है और इसके जिम्मेदार राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई समिति जिनको प्रतिमाह भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार 10 हजार की राशि गौठान के विकास के लिए देती है, किंतु गौठान की स्थिति देखकर यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने कांग्रेसीयों कि गौठान समिति बनाकर उनकी झोली भर रही है। डीपेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों की स्थिति बदहाल है, गोवंश के लिए ना ही चारे की व्यवस्था है, ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी, जो कोटना पानी भरने के लिए बनाया गया है वह सूखा है और पूर्ण रूप से कचरे से भरा हुआ है, गोबर खरीदी कर उसको महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से कम्पोस्ट खाद बनाना था किंतु उचित सामग्री की अनुपलब्धता एवम समय पर राशि नहीं मिलने के कारण वह भी अधूरा है एवम समूह की महिलाए भी कार्य करने में रुचि नहीं दिखा रही है । राज्य सरकार के द्वारा आ रही राशि को गौठान के विकास के लिए ना लगाते हुए इस महती योजना को ठंडे बस्ते में डालकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का माध्यम बन चुका है। अवनेंद्र साहू ने आगे बताया कि केंद्र सरकार के 15 वे वित्त से बने गौठान निर्माण और राज्य सरकार के द्वारा गौठान में एक रुपए का व्यय न करना गौठान की बदहाल स्थिति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार राज्य सरकार है एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई गौठान समिति जिम्मेदार है। गौठान में लाखो की लागत से बना बायो गैस संयंत्र शोपीस बना हुवा है।गौठान पहुंचे कार्यकर्ता में प्रमुख रूप से यतीश भूषण श्रीवास्तव, भीखम सिन्हा, खेदूराम, प्रद्युम्न नागरची, युवराज महेंद्र, वेदव्यास साहू, शिवराम साहू, धनेश्वर साहू, रघुनाथ ढीमर, वेद साहू, इंदल राम साहू एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

नये भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक बनेगा नया संसद भवन: रंजना

धमतरी। भारत की संसद की नई ईमारत का रविवार 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, विभिन्न धर्मों के प्रमुखों और साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक विधि विधान के साथ देश के संसद की इस नई ईमारत का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना की जिसे सत्य, न्याय और निष्ठा के प्रतीक स्वरूप स्थापित किया गया है, नई संसद में अखंड भारत का नक्शा, अंबेडकर-सरदार पटेल और चाणक्य की प्रतिमा समेत कई ऐसी चीजें उकेरी गई हैं, इस नए संसद भवन के बनने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धमतरी की विधायक रंजना डिपेंद्र साहू ने कहा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मंदिर 'नए संसद भवन'. आज यह भवन नए भारत के नए जोश, नई उमंग, नई सोच, नई दिशा व नई दृष्टि को प्रदर्शित करता है। नये भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक बनेगा यह वैभवशाली गौरवशाली संसद भवन और नए संसद भवन में लगा अखंड भारत का मानचित्र देश की सांस्कृतिक धरोहरों, लोक कल्याण की भावना और प्रतिबद्धता की ओर इंगित करता है जो भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाने के स्वप्न को भी दर्शाता है, यह संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है, जिसमें एक विकसित भारत को देखा जा सकता है। देशवासी जहां लोकतंत्र के इस नवीन भव्य मंदिर में नए भारत का उज्वल और स्वर्णिम भविष्य देख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की आंखों में बंधी पट्टी उन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रही है।

आगे श्रीमती साहू ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जब 'नए भारत का नया संसद भवन' राष्ट्र को समर्पित किया और राजधर्म, न्याय, निष्पक्षता, संप्रभुता, अक्षुण्णता एवं सामर्थ्य को साष्टांग दंडवत प्रमाण किया, तब वह क्षण ऐतिहासिक था। यह पल देश के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी अपने दोस्तों को बेच रहे देश की संपत्ति : खड़गे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने नौ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की संपत्ति अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। खड़गे ने कहा देश की संपत्ति को अपने मित्रों को बेचना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी अधिनियम है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपने दोस्तों को देश की संपत्ति और सार्वजनिक उपक्रमों की आगमन बिक्री सबसे बड़ा राष्ट्र-विरोधी अधिनियम है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से रोजगार छीन रही है। यह आरक्षण के रूप में भारत के गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से रोजगार के अवसर छीन रही है। इससे पहले, खड़गे ने सोमवार को सत्ता में नौ साल पूरे होने पर सरकार पर निशाना साधा था और महंगाई के जरिए लोगों की कमाई को लूटने का आरोप लगाया।

जनता गहलोत सरकार के कुशासन से परेशान : राठौर

नई दिल्ली। राजस्थान चुनाव के पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है और उनके केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार को फिर से दोहराने के कितने ही दावे करें, प्रदेश की जनता उनके कुशासन से परेशान है और अब उनका जाना तय है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी घोटालों की जांच होगी। भाजपा नेता ने कहा कि गहलोत और पायलट के बीच गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट के बीच जो भी समझौता हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता; अब प्रदेश की जनता तय करेगी कि उनकी (कांग्रेस की) विदाई में कौन सा संगीत बजाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि चार साल बाद इस समझौते के क्या मायने हैं?

केजरीवाल के लिए अध्यादेश के खिलाफ रास्ता आसान नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दलों के नेताओं ने उन्हें अपना समर्थन भी दिया। केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में इस मसले को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही एक राय है। दोनों दलों के नेता केजरीवाल पर हमलावर हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने माकपा नेताओं के साथ बैठक की थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने इस मुद्दे पर हर संभव दरवाजे पर दस्तक देकर खुद को उपहास का विषय बना लिया है। सचदेवा ने कहा, राजनीतिक जोकर की तरह केजरीवाल को उन नेताओं के दरवाजे पर दस्तक देते देखना आश्चर्यजनक है।

उद्धव ठाकरे पटना में विपक्षी दलों की बैठक में होंगे शामिल

मुंबई। शिवसेना (ठाकरे गुट) की पार्टी के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। साल 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई जा रही है। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों में मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके अगुवा नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए सीएम नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस संबंध में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, केवल शिवसेना ही नहीं सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पटना में होने वाली बैठक में जरूर शामिल होंगे।

दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो : ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में हुई जुनैद और नसीर की हत्या पर भी उन्हें बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा और दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने बंदी संजय के दावे पर भाजपा पर तीखा हमला किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि उनके पास सबूत नहीं हैं। जब सीएए का विरोध हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था तब सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तब सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए क्या हो रहा है।

राहुल ने अमेरिका में भारत सरकार और मीडिया पर साधा निशाना

सैन फ्रांसिस्को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के तीन शहरों के दौरे के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। उन्होंने 31 मई को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा, वे भगवान के साथ बैठ सकते हैं और चीजों को समझा सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक उदाहरण हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप मोदी को भगवान के बगल में बिठाते हैं, तो वह भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और भगवान भ्रमित हो जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। उन्होंने कहा, लोगों का एक समूह है जो सब कुछ समझता है। वे विज्ञान को वैज्ञानिकों को, इतिहास को इतिहासकारों को, युद्ध को सेना को समझा सकते हैं, और इसके मूल में सामान्यता है, वे वास्तव में कुछ भी नहीं समझते हैं।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत वह नहीं है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो एक ऐसी राजनीतिक सोच को बढ़ावा देना पसंद करता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी विकृति है। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा में मेरे लिए यह बहुत स्पष्ट हो गया कि इन चीजों को दिखाना मीडिया के हित में है, इससे भाजपा को मदद मिलती है। इसलिए यह मत सोचिए कि मीडिया में आप जो कुछ भी देखते हैं वह सच है। उन्होंने कहा, भारत वह नहीं है जो मीडिया दिखाता है। मीडिया को एक विशेष कहानी दिखाना पसंद है। वह एक ऐसी राजनीतिक कहानी को बढ़ावा देना पसंद करता है जिसका भारत की वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए, गांधी ने कहा, एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण हमें राजनीतिक रूप से कार्य करना मुश्किल हो रहा था और इसलिए, हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की,

लेकिन इसका असर बढ़ता ही गया।

राहुल गांधी ने कहा कि वे (कांग्रेस) सभी धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान और स्नेह रखने के मूल्यों में विश्वास करते हैं। अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों को नसीहत देते हुए गांधी ने कहा, आप इसी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप इन मूल्यों से सहमत नहीं होते तो आप यहां नहीं होते। अगर आप क्रोध, घृणा और अहंकार में विश्वास करते हैं, तो आप भाजपा की बैठक में बैठे होते। और मैं मन की बात करूंगा। कुछ महीने पहले केंद्र में आई भाषा की राजनीति के बारे में बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह किसी को भी क्षेत्रीय भाषाओं को धमकाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा, अगर कोई किसी भाषा पर हमला करता है, तो वह भारत पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होना जरूरी है। भाजपा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करेगी। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तब हम यह करेंगे। सेंगोल के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, गुस्से के प्रसार और नफरत जैसे मुद्दों का समाधान नहीं कर सकती है. गांधी ने रविवार को पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किए गए सेनगोल का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी वास्तव में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती है, इसलिए उन्हें राजदंड करना होगा।भाजपा के यह कहने के बाद विवाद खड़ा हो गया कि सेनगोल तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड था, जिसे 1947 में अंग्रेजों से सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं था।

मुस्लिमों की तरह ही सिख-ईसाई और दलित भी खुद पर हमला महसूस कर रहे

राहुल गांधी ने बुधवार सुबह भारतीयों से बातचीत की। जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो दलितों के साथ 1980 में हो चुका है। दरअसल, कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी ने पूछते हुए कहा कि मुस्लिमों को आजकल धमकियां मिल रही हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया। इतना ही नहीं पहले जो कभी बदलाव नहीं हुए, आज कल किए जा रहे है। यहां तक कि मुस्लिम बच्चों को उन मामले में जेल भेजा जा रहा है, जिसे उन्होंने किया ही नहीं है। बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि आप इस पर क्या भरोसा देना चाहते हैं? भारत में मुस्लिमों की स्थिति क्या है? आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जिस से भारत सामान्य स्थिति में लौट सके? राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं कह सकता हूं कि 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान'। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही सारे समुदाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों पर हमला हो रहा है और वह जो महसूस कर रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वहीं, 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। राहुल ने आगे कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। बल्कि नफरत को प्यार से दूर किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि भारत में कैसे नफरत बढ़ रही है। जबकि वहां के लोग बिल्कुल ऐसे नहीं है। वह एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं।

अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भड़की भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में उनके भाषण को लेकर आलोचना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं, तब उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है। राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि यह देश की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को धमकी दे रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन पर तीखा हमला किया और कहा कि जिन्ना की आत्मा राहुल गांधी में तब प्रवेश करती है जब वह विदेश में होते हैं। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके शरीर में जिन्ना की आत्मा या अल कायदा जैसे लोगों की सोच प्रवेश कर जाती है। मैं उन्हें भारत आने और किसी अच्छे ओझा से भूत भगाने का सुझाव दूंगा। राहुल गांधी की समस्या यह है कि वह आज भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे समावेशी विकास के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी सामंती जागीर को खत्म कर दिया है। नकवी ने कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र की तुलना वंशवाद से करते हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है और कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंग गम की तरह इस्तेमाल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए।

राहुल की हर यात्रा में भारत का अपमान : अनुराग ठाकुर

नईदिल्ली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो पीएम मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप पहले के भी भाषण देखेंगे तो वह भारत को राष्ट्र ही मानते ही नहीं है, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं। साथ ही वह भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्नचिह्न करते हैं। ठाकुर ने राहुल पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि आखिर उनकी यात्रा का मकसद क्या होता है? वह विदेश यात्रा से क्या पाना चाहते हैं? क्या विदेश में कीचड़ उछालना ही काम रह गया है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप अंतर देख सकते हैं जब-जब राहुल विदेश की यात्रा पर गए हैं उन्होंने भारत और देशवासियों पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि भारत की जो तरक्की हो रही है, साख बढ़ रही है उसको गिराने का काम लगातार राहुल कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पीएम मोदी की यात्रा पर नजर डालिए। पीएम ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान लगभग 24 पीएम और दुनिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और 50 से अधिक बैठकें की थीं। कई विदेशी मंत्री उन्हें लोकप्रिय नेता बताते हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा था कि पीएम मोदी बॉस हैं। उन्होंने कहा कि शायद यही बात राहुल को नहीं पची होगी, इसलिए वह विदेश में उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार हुआ था, तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी। अनुराग ठाकुर ने कहा शायद यही राहुल बताना चाह रहे थे कि उनकी सरकार में सिर्फ दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, जबकि आज सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत में विश्वकप खेलने से मना कर सकता है पाकिस्तान!

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष और सीईओ यह आश्वासन आने के लिए अभी लाहौर में हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में अपने मैचों के लिए हाइब्रिड मॉडल लागू करने पर जोर नहीं देगा। सूत्रों ने पुष्टि की कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और सीईओ ज्योफ एलार्डिस विशेषकर इसलिए लाहौर पहुंचे हैं ताकि वह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन हासिल कर सकें। पीसीबी के प्रमुख नजम सेठी ने स्पष्ट किया है कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी तो फिर उनकी टीम भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। इसके बाद ही आईसीसी के शीर्ष पदाधिकारी पाकिस्तान दौरे पर आए हैं।

सूत्रों ने कहा, 'आईसीसी और वनडे विश्व कप का मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर चिंतित हैं।' उन्होंने कहा, 'सेठी ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव हालांकि वनडे वर्ल्ड कप से पहले होने वाले एशिया कप के लिए दिया है लेकिन अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए यह मॉडल स्वीकार कर लिया जाता है तो पीसीबी पाकिस्तान के भारत में खेलने के सवाल पर आईसीसी से वनडे वर्ल्ड कप में भी इस मॉडल को लागू करने के लिए कह सकता है।' सेठी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि पाकिस्तान सरकार सुरक्षा कारणों से टीम को भारत भेजने की अनुमति नहीं देती है तो पीसीबी ऐसी स्थिति में आईसीसी से पाकिस्तान के मैच तटस्थ स्थान पर करवाने के लिए कहेगा। सूत्रों ने कहा, 'स्वाभाविक है कि आईसीसी और बीसीसीआई इस तरह की स्थिति नहीं चाहते क्योंकि इससे भारत-पाकिस्तान मैच और यहां तक कि टूर्नामेंट की सफलता भी प्रभावित होगी।'

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 347 अंक टूटा निफ्टी 18,600 के नीचे

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार तेजी से फिसलकर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 347 अंक टूटा। वहीं, निफ्टी में भी 99 अंकों की गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,534.40 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 346.89 अंक यानी 0.55 फीसदी टूटकर 62,622.24 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,876.77 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 62,401.02 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्स्श्व) के निफ्टी में 99.45 अंक यानी 0.53 फीसदी की गिरावट देखी गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 18,534.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,603.90 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,483.85 तक आया।

मार्च तिमाही में 6.1 फीसदी पहुंची भारत की जीडीपी

नईदिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 फीसदी का इजाफा हुआ। सरकारी डेटा ने बुधवार को बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का इसमें काफी योगदान रहा है और निजी निवेश में उत्साहजनक वृद्धि देखने को मिली है। 2022-23 के पूरे वित्त वर्ष के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर आ गई। जबकि वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4 फीसदी दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.4 फीसदी थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यह 6.3 फीसदी थी, और वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में यह 13.2 फीसदी थी। इससे पहले, 56 अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही की वृद्धि दर 5 फीसदी आंकी गई थी।

बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% पर पहुंचा

नईदिल्ली। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत रहा। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। लेखा महानियंत्रक ने केंद्र सरकार के 2022-23 के राजस्व-व्यय का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपये (अस्थायी) रहा है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। कैग ने कहा कि राजस्व घाटा जीडीपी का 3.9 फीसदी रहा है। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8 फीसदी रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश आम बजट में 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9 फीसदी पर सीमित करने का लक्ष्य रखा है।

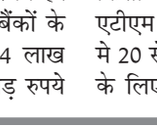

आरबीआई लाने जा रहा एलपीएसएस पेमेंट सिस्टम

नईदिल्ली। यूपीआई की सफलता के बाद अब केंद्रीय बैंक एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की योजना बना रहा है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नए पेमेंट सिस्टम का नाम 'लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम' (एलपीएसएस) होगा। नया पेमेंट सिस्टम पारंपरिक टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अलग होगा और इसे बहुत ही कम कर्मचारी कहीं से भी ऑपरेट कर सकेंगे। एलपीएसएस पेमेंट सिस्टम इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी परिस्थिति में पेमेंट सेटलमेंट किया जा सकेगा। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी भयावह घटनाओं में ये प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलपीएसएस पेमेंट सिस्टम को तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

भारत में विदेशी बैंकों का कारोबारी परिदृश्य

तमाल बंद्योपाध्याय

ऐसा लगता है कि एचएसबीसी इंडिया भारत में खुदरा बैंकिंग कारोबार से सिटीबैंक के निकलने के बाद मौजूद संभावनाओं का लाभ उठाने में जुट गया है। सिटीबैंक ने अपना खुदरा कारोबार ऐक्सिस बैंक को बेच दिया है। पिछले सप्ताह रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कि परिसंपत्ति के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा बैंक एचएसबीसी एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए 12 देशों में अपना कारोबार छोटा कर सकता है या बेच सकता है।

एचएसबीसी ऐसे समय में यह कर सकता है जब सिटी भारत सहित 14 बाजारों से कारोबार समेट कर उन खंडों में निवेश करना चाहता है जहां यह तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने की मजबूत स्थिति में है। तो क्या भारत में विदेशी बैंकों का कारोबारी परिदृश्य बदल रहा है? हां भी और नहीं भी। भारत में सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की सूची में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग एक तिहाई है मगर कारोबार में इनकी हिस्सेदारी बहुत छोटी है।

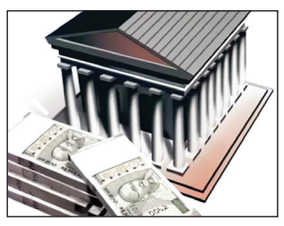

सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक (पेमेंट्स बैंक), सूक्ष्म वित्त बैंक (स्मॉल फाइनैंस बैंक) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं। मार्च 2022 तक 45 विदेशी बैंक थे जिनकी कुल 861 शाखाएं थीं। उनके एटीएम की संख्या 1,797 थी। बैंकिंग परिसंपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत, जमा रकम में 4.92 प्रतिशत और ऋण खाते में तो इससे भी कम मात्र 3.85 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 21 निजी बैंकों (नए एवं पुराने दोनों) की 37,872 शाखाएं और 75,543 एटीएम हैं। परिसंपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी 34 प्रतिशत, जमा रकम में 31.8 प्रतिशत और ऋण खाते में 37.8 प्रतिशत है। इसी तरह, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियों में 59.7 प्रतिशत, जमा रकम में 63.2 प्रतिशत और ऋण में 58.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन 12 बैंकों की देश में 84,256 शाखाएं हैं और 1,38,056 एटीएम देश भर में हैं। आंकड़ों के आधार पर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियां 127 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि निजी बैंकों की 73.3 लाख करोड़ रुपये हैं। विदेशी बैंकों की परिसंपत्तियां 13.7 लाख करोड़ रुपये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के ऋण खाते का आकार क्रमश: 70.44 लाख करोड़ रुपये और 45.63 लाख करोड़ रुपये है। विदेशी बैंकों के ऋण खाते महज 4.64 लाख करोड़ रुपये के हैं। शाखाओं एवं एटीएम की संख्या के आधार पर बात करें तो डीबीएस बैंक इंडिया की उपस्थिति सबसे अधिक है। लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण करने के बात इसकी कुल 592 शाखाएं हो गई हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड की 100, सिटीबैंक (ऐक्सिस को खुदरा कारोबार बेचने से पहले) की 35, एचएसबीसी की 26 और डॉयचे बैंक एजी की 17 शाखाएं हैं।

डीबीएस बैंक के 1,021 से अधिक एटीएम हैं, जबकि सिटीबैंक के एटीएम की संख्या 488 है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी और डॉयचे बैंक की क्रमश: 167, 74 और 32 शाखाएं हैं। इनके बाद अन्य किसी भी अन्य विदेशी बैंक की शाखाओं या एटीएम की संख्या दो अंक में नहीं है। भारत मे 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए कुल ऋण आवंटन का 40 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय बैंकों की तरह ही प्राथमिक क्षेत्र को देना जरूरी है। भारत में सबसे बड़े विदेशी बैंक की कुल आवंटित ऋण और जमा रकम में 1 प्रतिशत भी हिस्सेदारी नहीं है मगर मुनाफे की बात करें इन बैंकों की हिस्सेदारी आनुपातिक रूप से काफी अधिक है। इसका कारण क्या है? स्थानीय बैंकों की तुलना में उनका कारोबारी ढांचा अलग है। प्रत्येक श्रेणी के बैंकों के बहीखाते में नहीं दिखने वाली परिसंपत्तियां या देनदारियां जैसे डेरिवेटिव तस्वीर और साफ करते हैं। इस खंड में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 49.7 प्रतिशत है जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी क्रमश: 31.8 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत है। जमा में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम होने के बावजूद वे छोटे चालू एवं बचत खातों (कासा) के लिए स्थानीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

स्वर्ग जैसे शासन का आश्वासन फिर भी विपक्ष विहीन उद्घाटन

संजय तिवारी

यह 1912-13 की बात है। उस समय 1911 में किंग जार्ज पंचम का दिल्ली दरबार सज चुका था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का निर्णय भी हो चुका था। भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के लिए नया भवन और सचिवालय पर काम शुरु हो चुका था। उसी समय यह निर्णय भी हुआ कि एक इम्पिरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा। 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने निर्णय लिया था कि कानून बनाने में भारत के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसे बहुचर्चित मार्ले मिन्टो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की तर्ज पर यहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे दो चैम्बर बनाने का निर्णय हुआ था जिसमें एक में राजा रजवाड़ों तथा विशिष्ट लोगों को नियुक्त किया जाना था तो दूसरे में सीमित मताधिकार के जरिए जनप्रतिनिधियों को शामिल करना था। इसे लागू करने से पहले एक पार्लियामेन्ट का होना जरूरी था। इसलिए 1912-13 में नयी दिल्ली की रचना कर रहे दो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी दी गयी कि वो इसके लिए अपना अपना डिजाइन प्रस्तुत करें। एडविन लुटियन जहां गोल घेरे में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस (बाद में पार्लियामेन्ट) का भवन बनाना चाहते थे, वहीं हर्बर्ट बेकर इसे त्रिभुज आकार में निर्मित करना चाहते थे। हर्बर्ट बेकर उसे वहीं बनाना चाहते थे जहां आज पुराना संसद भवन है जबकि लुटियन इसे कहीं और बनाना चाहते थे। खैर दोनों की एक एक बात मान ली गयी जहां लुटियन का गोल घेरे वाला डिजाइन फाइनल हुआ वहीं बेकर जहां बनाना चाहते थे, उस जगह पर ही उस भवन को बनाने का निर्णय किया गया। फरवरी 1921 में उस भवन का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर के हाथ से करवाया गया। करीब सात साल में यह भवन बनकर तैयार हुआ और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने भले ही भारत के लोगों को कानून निर्माण में शामिल करने के लिए इस नये भवन को बनाया था लेकिन 1929 में भगत सिंह ने इसमें घुसकर बम फेंक दिया जो इस बात की निशानी था कि भारत के लोग ब्रिटिश रहमो करम पर अपनी भागीदारी नहीं चाहते थे। हालांकि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस के उद्घाटन के बाद हुए रिसेप्शन में राजस्थान और पंजाब के कई रजवाड़ों को निमंत्रित किया गया था। अपनी अपनी रॉल्स रॉयस में पगड़ी और साफा बांधे राजे रजवाड़े आये भी लेकिन क्रांतिकारियों और आम जनता के मन मानस में तो कुछ और ही चल रहा था। वह था पूर्ण स्वराज। खैर, इतिहास के उतार चढाव के साथ 1952 में बतौर पार्लियामेन्ट (संसद) के रूप में लुटियन्स के उसी गोल घर को स्वीकार कर लिया गया और स्वतंत्रता के लगभग सत्तर साल उसी गोल घर से भारत के विधायी कार्य संपन्न होते रहे। समय के साथ वह भवन धीरे धीरे कमजोर और अप्रांसगिक भी होने लगा था। यह भी एक संयोग ही कहा जाएगा कि जिस समय इस संसद का उद्घाटन हुआ और उसमें रिसेप्शन रखा गया उस समय ही इसकी छत का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया था। इसके बाद कई ऐसे उदाहरण बताये जाते हैं जब इस भवन की भीतरी कमजोरी उजागर हो जाती थी। इसलिए यूपीए सरकार के समय में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने नये संसद भवन की चर्चा शुरु की थी। हालांकि उस समय सरकार ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रस्ताव को एकदम से खारिज भी नहीं किया गया। नये संसद भवन की जरूरत तो थी ही इसलिए मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2020 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। लुटियन्स दिल्ली में कई बड़े निर्माण का प्रस्ताव किया गया। इसमें थल सेना भवन को यहां से बाहर ले जाने, शास्त्री भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन को तोड़कर उनकी जगह नया भवन बनाने तथा इंदिरा गांधी कलाकेन्द्र की जमीन पर केन्द्रीय मंत्रालय के कार्यालय बनाने का काम सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। इस परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास को भी राष्ट्रपति भवन परिसर में ही लाने का प्रस्ताव था। सिर्फ वाइसरॉय हाउस (राष्ट्रपति भवन) को छोड़कर सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने पर लुटियंस के सभी निर्माण धरोहर में बदल दिये जाएंगे।

नीतीश के प्रयास पर बड़ा प्रश्नचिन्ह

अजय सेठिया

विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार को दी गई जिम्मेदारी के बीच कांग्रेस ने यूपीए को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार सभी गैर भाजपा दलों को एक मंच पर लाकर लोकसभा चुनाव में हर सीट पर भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिशों में जुटे हैं। अनुभवी कांग्रेस को पता है कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, जिनका आधार कांग्रेस की जमीन पर ही खड़ा है। न वे कांग्रेस के साथ किसी तरह गठबंधन करना चाहेंगे, न कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करके अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहेगी।

नीतीश कुमार यह मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक विपक्षी एकता में शामिल हो जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वह जेडीएस को शामिल करते थे। चुनाव नतीजों के बाद और खासकर संसद की नई इमारत के उद्घाटन के बाद साफ़ हो गया कि बदली परिस्थिति में जेडीएस एनडीए में शामिल होने का प्रयास करेगी।

नीतीश कुमार जिन पांचो मुख्यमंत्रियों के दलों को विपक्षी एकता का हिस्सा बनाने की उम्मीद पाले हुए हैं, वे सभी कांग्रेस की जमीन पर ही खड़े हैं। एक एक कर अपन सभी की समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी की बात करते हैं। वह मूल रूप से कांग्रेसी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मन से कम्युनिस्टों का मुकाबला करने में अक्षम है, तो उन्होंने कांग्रेस की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस खड़ी करके कम्युनिस्टों से सत्ता छीन ली। बंगाल में अब कम्युनिस्ट और कांग्रेस एकजुट हैं, लेकिन ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा है। वह कम्युनिस्ट पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन सागरदीघी विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी थोड़ी नर्म पड़ी है। इसका कारण यह है कि ममता को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ वापस जा रहा है, जो उनके लिए खतरे की घंटी है।

कांग्रेस को एहसास है कि ममता सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़कर नहीं गई थी। वह इसलिए कांग्रेस छोड़कर गई थी क्योंकि बंगाल में कांग्रेस वामपंथियों से उस तरह नहीं लड़ रही थी, जैसे लड़ना चाहिए था। ममता ने कांग्रेस छोड़ने के बाद भी सोनिया गांधी के साथ संबंध बनाए रखे थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह भाजपा के साथ इसलिए गई थी, क्योंकि तब बंगाल में ममता और भाजपा के हित साझा थे। ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाकर कम्युनिस्टों को हराने का कांग्रेस का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन अब भाजपा को रोकने के कांग्रेस और ममता के हित साझा हैं। इसलिए इन पांच मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ ममता बनर्जी को ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता गया था।

अरविन्द केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, इन चारों मुख्यमंत्रियों की बात अलग है। ये चारों कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि चारों को पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब राजनीतिक आत्महत्या होगा। अरविन्द केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर कब्जा करने से राजनीति की शुरुआत की थी। अब तक वह कांग्रेस से दो राज्य छीन चुके हैं, और दो अन्य राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। वह मजबूरी में अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से मदद मांगने गए हैं। वह कांग्रेस की मदद से दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण हासिल करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल का सपना सारे देश में कांग्रेस का विकल्प बनना है, उनका लक्ष्य भाजपा का विकल्प बनने का नहीं है। वह यह भी समझने लगे हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह वह राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकते। जहां जहां कांग्रेस के सामने भाजपा मजबूत स्थिति में है, वहां केजरीवाल की दाल नहीं गल रही। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इसलिए केजरीवाल की दूसरी सोच यह बन रही है कि विपक्षी एकता में उन्हें पूरे देश में पचास सीटें भी मिल जाती हैं, तो वह दूसरों की जमीन पर खेती काट सकते हैं। अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल ने कांग्रेस से मदद माँगी है, लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की फिलहाल नहीं सोच रही।

तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने कांग्रेस की जमीन पर ही कब्जा किया है। अगर वे कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं, तो कांग्रेस कब्जाई गई जमीन पर हिस्सा मांगेगी। इसलिए ये तीनों दल कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। सबसे पहले तेलंगाना की बात कर लेते हैं। अलग राज्य की मांग करते हुए टीडीपी से निकल कर टीआरएस बनाने वाले चन्द्रशेखर राव पूरी तरह केजरीवाल के पदचिन्हों पर चल कर रेवड़ियां बांट रहे हैं। उनकी शासन चलाने की तानाशाहीपूर्ण शैली के खिलाफ कांग्रेस के तीन बड़े नेता इस समय प्रदेश में पदयात्राएं कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस टीआरएस की मुख्य प्रतिद्वन्दी पार्टी है, वह टीआरएस के साथ चुनावी गठबंधन कैसे कर सकती है। नीतीश कुमार ने भले ही चन्द्रशेखर राव को गठबंधन में लाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं है, उसने समान्तर रणनीति के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राजशेखर रेड्डी की बेटी और जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी है। डीके शिवकुमार ने 29 मई को उनसे मुलाक़ात भी की है।

हालांकि शर्मिला का तेलंगाना में ज्यादा प्रभाव नहीं है, उनके पिता राजशेखर रेड्डी ईसाई थे और खुद उन्होंने एक ब्राह्मण से शादी की है। तेलंगाना के ईसाईयों में जरुर शर्मिला का कुछ प्रभाव है, लेकिन ब्राह्मण से शादी के कारण रेड्डी उनके साथ नहीं है। हालांकि कांग्रेस अगर यह समझती है कि शर्मिला से गठबंधन के चलते उन्हें रेड्डी वोट मिल जाएंगे, तो यह संभव होते नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस केसीआर को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

जहां तक जगन मोहन रेड्डी का सवाल है, तो सोनिया गांधी से सीधे टकराव के चलते उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई थी, उन्होंने राज्य में कांग्रेस को लगभग खत्म ही कर दिया है। वह कांग्रेस के साथ आंध्र की जमीन साझा नहीं करना चाहते। इसलिए वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क बनाए हुए हैं और हर मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने बाकी विपक्षी दलों की तरह नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकाट भी नहीं किया। यहां एक पेच है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का सीधा मुकाबला चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ है, 2019 में उन्होंने टीडीपी को हरा कर ही सत्ता हासिल की है। आंध्र प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां की दोनों बड़ी पार्टियां वाईएसआर और टीडीपी मोदी के साथ खड़े होने का प्रयास कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मोदी ने अभी उनके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं। अगर मोदी उनके लिए दरवाजे नहीं खोलते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी के विपक्षी एकता में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। मोदी को जगन मोहन रेड्डी के साथ बना रहना बेहतर विकल्प लग रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जरुर विपक्षी एकता में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जमीन वैसे भी खिसक चुकी है। बाकी बचे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने 1998 में भाजपा से गठबंधन करने के लिए ही 1997 में जनता दल से अलग हो कर अपने पिता बीजू पटनायक के नाम पर बीजू जनता दल बनाया था। भाजपा के साथ गठबंधन करके ही मार्च 2000 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा के साथ गठबंधन से ही वह 2004 में दुबारा मुख्यमंत्री बने, 2009 में वह एनडीए से अलग हो गए, लेकिन 2014 से वह हर संकट की घड़ी में एनडीए सरकार के साथ खड़े रहे हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे, तो नवीन पटनायक ने उन्हें दो टूक कह दिया था कि न तो वह बीजू जनता दल का जनता दल में विलय करेंगे, न विपक्षी एकता में शामिल होंगे। बीजू जनता दल ने नए संसद भवन के उद्घाटन का भी बायकाट नहीं किया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

कृष्णोपनिषद्

यह उपनिषद् अथर्ववेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसका शुभारम्भ मुनिगणों एवं भगवान् के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। जिसमें भगवान् राम के द्वारा कृष्णावतार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार भगवान् के विविध लीला-विग्रह ही कृष्णावतार के समय के विभिन्न पात्रों के रूप में अवतरित हुए हैं। निष्कर्षत: कहा गया है कि उन भगवान् श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं समस्त वैकुण्ठधाम को पृथिवीतल पर अवतरित कर लिया है, जो भी मनुष्य इस तरह उन भगवान् को जानता है, वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बन्धनों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी फलश्रुति के साथ यह उपनिषद् पूर्ण होती है।

हे देव! हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनें, आँखों से कल्याणकारी (दृश्य) देखें, हम ह्रष्ट-पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बितायें। महान् कीर्ति सम्पन्न देवराज इन्द्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्टनेमि (जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके), तार्क्ष्य (गरुड़) तथा बृहस्पतिदेव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शान्ति हो ।

सर्वांग सुन्दर, सच्चिदानन्द स्वरूप, महाविष्णु के अवतारी) श्री रामचन्द्र जी को देखकर वनवासी मुनिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए। (उन्हें धरती पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश होने पर) ऋषियों ने उनसे (राम से) कहा- हम सब (धरती पर अवतरित होने को अच्छा नहीं मानते हैं। हम आपका आलिंगन (अत्यधिक निकटता) चाहते हैं। (भगवान् ने कहा- हमारे) अन्य अवतार कृष्णावतार में तुम सभी गोपिका बनकर मेरा आलिंगन (अतिसंत्रिकटता) प्राप्त करो। (ऋषियों ने पुन: कहा- हमारे) जो अन्य अवतार हों, (उनमें) हमें गोप-गोपिका बना दें। आपका सान्निध्य प्राप्त करने की स्थिति में हमें ऐसा शरीर (गोपिका आदि) धारण करना स्वीकार्य है, जो आपका स्पर्श सुख प्रदान कर सके। रुद्र आदि सभी देवों की यह स्नेहयुक्त प्रार्थना सुनकर स्वयं आदि पुरुष भगवान् ने कहा- हे देवो! मैं अपने अंग-अवयवों के स्पर्श का अवसर तुम्हें निश्चित रूप से प्रदान करता रहूँगा। मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा।

क्रमश: ...

विश्व दुग्ध दिवस

डॉ. शंकर सुवन सिंह

दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है और ये हमारी डाइट का कितना जरूरी हिस्सा है। इस बात को समझाने और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए जागरुक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है।

दूध मानव जीवन के खान पान का विशिष्ट अंग है। दूध के बिना स्वास्थ्य अधूरा है। दूध संपूर्ण आहार है। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है, जो मादाओं के दुग्ध ग्रन्थियों द्वारा बनाया जता है। गाय के दूध में प्रति ग्राम 3.14 मिली ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। गाय का दूध पतला होता है। जो शरीर मे आसानी से पच जाता है। स्तनधारियों से प्राप्त दूध शाकाहार है या मांसाहार ये विवाद बड़ा पुराना है। वेगन मिल्क की परिभाषा जब से आई वैसे ही दूध शाकाहार और मांसाहार के बीच फंस गया। इस द्वन्द को इस प्रकार समझें- जब स्तनधारी प्राणियों के बच्चे गर्भ में पलते हैं तब वो अपनी खुराक अपनी माँ के द्वारा ली गई खुराक से पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्भ में पलने और माँ के स्तन पान से बच्चा मांसाहारी नहीं हो जाता है। ये तो वही बात हुई कि जल शाकाहारी है या मांसाहारी। जल प्रकृति प्रदत्त है। जल पृथ्वी के नीचे से आता है न कि पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सभी को जल की आवश्यकता होती है। तभी तो कहा गया है जल ही जीवन है। मैं आपसे पूछता हूँ जल शाकाहार है या मांसाहार ? प्रकृति प्रदत्त चीजों के साथ मनुष्य को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि प्रकृति प्रदत्त सभी चीजें शाकाहार की श्रेणी में आती हैं। सिर्फ ये कहना कि पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें शाकाहर हैं और जानवरों से प्राप्त चीजें मांसाहार हैं, ये गलत होगा। स्तनधारियों का दूध देना प्रकृति प्रदत्त है ये शाकाहार श्रेणी में आता है। दूसरे शब्दों में मांस पर निर्भर रहने वाला मांसाहारी और पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहने वाला शाकाहारी कहलाता है। प्रकृति प्रदत्त चीजें यदि मांस जैसे भोज्य पदार्थ पर निर्भर हैं तो भी वह मांसाहारी की श्रेणी में आएँगे। जैसे बहुत से पेड़ पौधे कीट पतंगों को अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे मांसाहारी की श्रेणी में आएँगे। जानवरों से प्राप्त गोबर, मूत्र, आदि मांस की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतएव इनका उपभोग करने वाला मांसाहारी कैसे हो गया ? इसी प्रकार स्तनधारियों से प्राप्त होने वाला दूध मांस तो नहीं है फिर इसका उपभोग करने वाला मांसाहारी कैसे हो गया? अतएव दूध को पीने वाला दूधाहारी कहलाएगा। जल को पीने वाला जलाहारी कहलाएगा। फल को खाने वाला फलाहारी कहलाएगा। इसी प्रकार साग सब्जी को खाने वाला शाकाहारी कहलाएगा। दूध को शाकाहार कहने में आपत्ति तब से होने लगी है जब से देश में वीगनिस्म (वेगन मिल्क) के बारे में जागृति आने लगी। वीगनिस्म, फूड प्रोसेसिंग की देन है। फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत पेड़ पौधों से प्रात चीजों की प्रोसेसिंग करके वेगन मिल्क का निर्माण होता है। वीगन मिल्क पौधे आधारित दूध होते हैं। जिसमें कम मात्रा में फैट पाया जाता है। जैसे सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, कैश्यू मिल्क, बादाम का दूध, ओट्स मिल्क आदि।

भारत विरोधी मंसूबों के समर्थक हैं अर्दोआन

आनंद कुमार

तुर्किये में हाल में हुए चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी कमाल कलचदारलू को हराकर जीत हासिल की है। विनाशकारी भूकंप और जीवन यापन के संकट जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अर्दोआन प्रचार अभियान को मजहब आधारित राष्ट्रवाद पर केंद्रित करने में कामयाब रहे, जो बहुत से मतदाताओं की सोच से मेल खाता था। शासन तंत्र पर उनके नियंत्रण और रूस जैसी विदेशी ताकत के समर्थन ने भी उनकी जीत में भूमिका निभाई। अर्दोआन पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है, पहले प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 2003 से राष्ट्रपति के रूप में। उन्होंने 2017 में एक जनमत संग्रह के जरिये राष्ट्रपति पद की भूमिका को महज औपचारिक के बजाय एक शक्तिशाली पद में तब्दील कर दिया, जिससे तुर्किये में संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति का पद कार्यकारी हो गया। अर्दोआन की पार्टी जस्टिस ऐंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) ने राजनीतिक संस्थानों को खोखला कर दिया, मीडिया को वश में कर लिया और सत्ता पर मजबूत पकड़ के लिए सैन्य कमान को फिर से आकार दिया है। कलचदारलू के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य राष्ट्रपति को कार्यकारी के पद से हटाना और एक मजबूत संसदीय प्रणाली को बढ़ावा देना था। उन्होंने दक्षिणपंथी मतदाताओं से सीरियाई शरणार्थियों को वापस उनके वतन भेजने की वकालत करने की भी अपील की। हालांकि, चुनाव से पहले जनमत सर्वेक्षणों में अग्रणी होने के बावजूद कलचदारलू अंतत: हार गए।

समर्थकों द्वारा अर्दोआन एवं एकेपी की जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन उन्हें तुर्किये और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचकों की आपत्तियों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक नीतियों, भूकंप के बाद सुस्ती से राहत कार्यक्रम और लोकतांत्रिक संस्थानों के क्षरण की वजह से अर्दोआन की आलोचना हुई है। कई लोगों को उम्मीद थी कि कलचदारलू की जीत एक ज्यादा लोकतांत्रिक और समृद्ध तुर्किये का निर्माण करेगी, जो पश्चिमी मूल्यों के साथ संबंध स्थापित करेगा और यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि, अर्दोआन की जीत बताती है कि तुर्किये के अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहने की संभावना है, जिसके तहत यह विदेशी मामलों में बेहद टकराव वाला रुख अपनाता है और रूस जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अर्दोआन के व्यक्तिगत संबंध यूक्रेन पर क्रेमलिन के युद्ध के चलते भी बचे रहे। रूसी ऊर्जा आयात पर भुगतान के स्थगन से तुर्किये की बदहाल अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से इस साल अर्दोआन को अपने प्रचार अभियान पर दिल खोलकर खर्च करने में मदद मिली। तुर्किये यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित है और नाटो में इसकी भूमिका के कारण इसके चुनावी नतीजों का महत्व सीमाओं से परे है। अर्दोआन की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है, जैसे नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के खिलाफ वीटो करना और रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना, जिसके कारण अमेरिकी अगुआई वाली फाइटर जेट परियोजना से इसे हटा दिया गया। हालांकि तुर्किये ने वैश्विक खाद्य संकट के दौरान यूक्रेनी अनाज लदान की सुविधा जैसे समझौतों में बिचौलिए की भूमिका भी निभाई है।

जैसे ही अर्दोआन तुर्किये के राष्ट्रपति के रूप में अपना नया कार्यकाल शुरू करेंगे, उन्हें कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की बदहाल अर्थव्यवस्था और जीवन यापन का संकट अर्दोआन के लिए तत्काल एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती मुद्रास्फीति और घटती क्रयशक्ति ने तुर्किये के लोगों को प्रभावित किया है। इस संकट से निपटना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी उच्च प्राथमिकता होगी। अर्दोआन को अनियंत्रित मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने की जरूरत है। ब्याज दरों की कटौती से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की उनकी रूढ़िवादी नीति को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। आर्थिक स्थिरता बरकरार रखते हुए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना उनके प्रशासन के लिए जरूरी होगा। तुर्किये के नाटो सहयोगी, विशेष रूप से अमेरिका स्वीडन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ वीटो हटाने के लिए उत्सुक हैं। तुर्किये के उन लोगों के प्रत्यर्पण की मांग, जिन पर कुर्द उग्रवादियों से संबंध होने का संदेह है, ने स्थिति को जटिल बना दिया है। अर्दोआन को इन तनावों को दूर करने और एक समाधान खोजने की आवश्यकता होगी। तुर्किये को सीरिया की सीमा पर बाड़ लगाने की भी जरूरत है। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान विपक्षी ताकतों को अर्दोआन के समर्थन के कारण पड़ोसी देश सीरिया के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। तुर्किये ने उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान चलाया और वहां अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। रूसी-मध्यस्थ वार्ता सहित संबंधों को सुधारने के प्रयास राजनयिक संबंधों को अब तक सामान्य बनाने में विफल रहे हैं।

अर्दोआन के नेतृत्व में तुर्किये ने कुछ खास मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया है, जिसमें कश्मीर पर रुख भी शामिल है। यह ईरान और मलयेशिया के साथ उस समूह का भी हिस्सा है, जो इस्लामी दुनिया में नेतृत्व का दावा करना चाहता है, जो अक्सर भारत के खिलाफ रहता है। भूकंप के बाद सहयता के बावजूद यह देखा जाना बाकी है कि भारत के प्रति उसके रवैये में बदलाव आता है या नहीं। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता आज भले ही तुर्किये में चलन में नहीं हो, लेकिन उनका राष्ट्रवाद आज भी प्रतिध्वनित हो रहा है। अर्दोआन को रूढ़िवादी मतदाताओं का समर्थन हासिल है, जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर स्थापित मुल्क में इस्लाम को बढ़ाने और वैश्विक राजनीति में तुर्किये के प्रभाव को बढ़ाने के उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। जैसा कि तुर्किये अपना 100वां जन्मदिन मना रहा है, यह खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है, अर्दोआन के निरंतर नेतृत्व ने इसकी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों को आकार दिया है। पश्चिमी देशों एवं मास्को के साथ चुनावी नतीजों के दूरगामी परिणाम होंगे और व्यापक पश्चिमी एशियाई क्षेत्र उसकी भावी दिशा को करीब से देख रहे हैं।

बापू की दिनचर्या

स्वाध्याय और लेखन

स्नान के बाद हाथकते, बुने और धुले खादी के परिधान में बापू अपनी कुटिया में प्रवेश करते। दिन के भोजन से पूर्व का उनका यह समय यद्यपि किसी कार्य-विशेष के लिए नियत नहीं था, तथापि सामान्यत: उस समय वे नई भाषाएँ सीखते और पत्रादि लिखते। स्वाध्याय और लेखन का बापू का यह क्रम दूसरे क्षणों में भी चलता। उदाहरणार्थ—यरवदा-जेल में सन् 22 में वे सुबह साढ़े छह बजे स्वाध्याय करते तो कभी भोजन के समय भी । सन् 22 में वहाँ वे दिनभर में कुल मिलाकर छह घंटे स्वाध्याय करते। बिहार-यात्रा में प्रात:कालीन प्रार्थना के बाद उनका स्वाध्याय का क्रम चलता तो सेवाग्राम में सन् 45 में रोगी-सेवा के बाद और मालिश से पूर्व साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक लेखन कार्य। सन् 1944 में अस्वस्थता के कारण आगा खाँ जेल से रिहाई के बाद, राजाजी के विशेष अनुरोध पर उन्होंने एक मास तक विश्राम करना स्वीकार किया। सार्वजनिक जीवन से भी उन दिनों उन्होंने मुक्ति ले ली। उन दिनों अवकाश के क्षणों का उपयोग वे स्वाध्याय में करते और यह क्रम सुबह के बजाय दिन में ढाई से तीन बजे तक नियमित रूप से चलता। बापू स्वाध्याय और लेखन जितना किया, उतना शायद कोई दूसरा व्यक्ति कर सकेगा। अत्यधिक कार्यव्यस्तता के बीच भी उन्होंने खूब पढ़ा और लिखा। वे वृद्ध हो चले थे, किंतु उन्हें इसका भान ही नहीं था। सन् 1932 में यरवदा जेल में घनश्यामदासजी बिड़ला से उन्होंने यह बात कही थी और अपने को पाठशाला का विद्यार्थी बताया था। यही कारण है कि उन दिनों उर्दू का अध्ययन करते हुए वे तमिल, तेलुगु और बंगला जैसी भाषाएँ सीखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। अंतिम दिन तक नई भाषा, लिपि? और बोली सीखने का उनका क्रम चलता रहा। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में सन् 1904 में ही अपना साप्ताहिक हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी-चार भाषाओं में एक साथ प्रकाशित करना शुरू किया और वहाँ के भारतीयों के बीच जनता का कार्य गुजराती तथा हिंदी जैसी स्वभाषाओं में विशेष रूप से किया। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के तमिल भाइयों की निकटता प्राप्त करके उन्होंने तमिल का अध्ययन भी किया। अफ्रीका से भारत लौटने पर जनता की भाषा के द्वारा उन्होंने जनता का कार्य शुरू किया।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

जेसीसीजे का 14 नहीं एक कार्यकर्ता ने छोड़ी पार्टी : विजय झाड़ी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 14 कार्यकर्ताओं के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसीजे) छोड़ने पर पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने बुधवार को कहा कि, जेसीसीजे का सिर्फ एक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुआ है, 14 का सदस्यता लेने का दावा झूठा है। कहा कि, भाजपा के नेता प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को दिखाने के लिए झूठ परोस रहे हैं। ऐसे में कही के भी लोगों को लाकर भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं और उन्हें जेसीसीजे का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। विजय झाड़ी ने कहा कि, ओम माथुर के बीजापुर दौरा पूरी तरह से विफल रहा। उनके दौरे पर बीजापुर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी नदारद रहे। कहा की भाजपा और उनके नेता बीजापुर में पूरी तरह लाचार और बेबस हैं। जनता कांग्रेस (जे) की बढ़ती लोक प्रियता से डरे भाजपाई उसकी छवि खराब करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है की केवल एक निष्क्रिय कार्यकर्ता केजी सुधारक जिन्हें पार्टी ने हटा दिया था। उसने ही भाजपा में प्रवेश किया है।

कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन 2 जून को, हजारो कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा

जगदलपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अपना पहला संभागीय सम्मेलन का आयोजन 2 जून को जगदलपुर के कृष्णा गार्डन में आयोजित किया है। इस सम्मेलन में बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों के दो हजार से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं के बैठने से लेकर खाने और रूकने का शानदार इंतजाम किया जा रहा है। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कांग्रेस जगदलपुर में संभागीय सम्मेलन के जरिए करने जा रही है। इस सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, चंदन यादव, बस्तर प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का, विधायक विकास उपाध्याय जैसे बड़े नेता सीधे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते राज्य सरकार की योजनाओं के दम हुए उन्हें पर लोगों के बीच जाने, मोदी सरकार के कामों की विफलाताओं को उजागर करने, एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का संकल्प दिलवाया जाएगा।

खोए हुए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे, पुलिस ने चलाया अभियान

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती में पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे करीब 60 लोगों के मोबाइल थे, जो उनको वापस मिले। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इन मोबाइल को तलाश कर बरामद किया। इनमें से कई मोबाइल चोरी हो गए थे, तो कई खो गए थे। बरामद मोबाइल की कीमत करीब नौ लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अफसरों ने बताया कि, लोगों के मोबाइल लौटाने के लिए एक प्रयास, आपका गुम मोबाइल, आपके पास नाम से अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक एमआर अहीरे ने बताया कि, अभियान के तहत आवेदकों से उनके गुम मोबाइल के मिले आवेदन सभी थाना में दर्ज कराए गए थे। इन्हें बरामद कर लोगों को लौटा दिया गया। उन्होंने कहा की किसी भी दुकानदार या व्यक्ति से बिना बिल जिसमें आईएमइआई नंबर ना लिखा हो, उसे ना खरीदें। हो सकता है वह मोबाइल चोरी का हो या किसी अन्य घटना में उपयोग किया गया हो। इस तरह के कृत्य में शामिल होना पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

दुर्ग जिले में एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने किया पदभार ग्रहण

दुर्ग। जिले में नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। एसपी सिन्हा का दुर्ग चौथा जिला है। जहां एसपी के रुप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे है। इसके पूर्व सुकमा , बिलासपुर, कांकेर में एसपी के रुप में अपनी सेवाएं दे चुके है। एसपी सिन्हा ने सेक्टर 6 स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम में पत्रकारों से भी मुलाकात किया। इस दौरान एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि वे वर्ष 2014 बैच के आईपीएस है। सिन्हा प्रशिक्षु के रुप में पहली बार दुर्ग में ही पोस्टिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा अपराधियों में नकेल कसने अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने का प्रयास होगा। एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर लोगों में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। आईपीएस बनने से पहले शलभ सिन्हा बालको में प्राइवेट नौकरी किया करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा कोरबा खुसमुंडा में 12 वीं तक पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई रायपुर से पूरा किया।

बालोद जिले में गजराजों में मचाया उत्पाद,रात भर जग रहे ग्रामीण

बालोद। बालोद जिले में लगातार हाथियों के दल उत्पात मचा रहे हैं। ग्राम बरही में रात 9 बजे के करीब दंतैल हाथी गांव पहुंचा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। फ्लिहाल दंतैल हाथी ने कोई हानि नहीं पहुंचाई है। वन अमले ने पारा, स्वरम रिसोर्ट, बरही, कांडे, नारागांव, किनारगोन्दी, नर्रा, रानीमाई मंदिर आदि क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है।

दिल्ली में तैयार हो रही प्रदेश के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति

■ **जगदलपुर और अंतागढ़ पर खास फोकस माथुर और जामवाल को मिला फ्री हैंड**

जगदलपुर। अब तक माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के भरोसे अरुणोदय करने वाली है, मगर अब राज्य के लिए पार्टी ने रणनीति बदल दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को चुनावी रणनीति बनाने, जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए फ्री हैंड मिल गया है। विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे में प्रदेश अध्यक्ष श्री साव की राय को महत्व तो दिया जाएगा, मगर अंतत: होगा वही, जो श्री माथुर और श्री जामवाल चाहेंगे। श्री माथुर को जहां आदिवासी बहुल संभागों में कार्यकर्त्ताओं की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं मैदानी जिलों की जवाबदेही श्री जामवाल को सौंपी गई है।

भाजपा की चुनावी रणनीति की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए चेहरे भी तलाशे जाने लगे हैं। भाजपा के केंद्रीय स्तर के संगठन – शिल्पी ओम प्रकाश माथुर और अजय जामवाल को छत्तीसगढ़ के किए संगठन की स्वतंत्र जवाबदारी दी गई है। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे पार्टी नेतृत्व के हाथों में है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों की पूरी रणनीति केंद्रीय भाजपा कार्यालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के 9 सफ्दरजंग लेन तुगलक रोड नई दिल्ली स्थित बंगले में बन रही है। इन्हीं दोनों जगहों से छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर विजय पताका फ्हराने की रूपरेखा तैयार करने की जद्दोजहद चल रही है। मानसून के पहले बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों का अंतिम मूल्यांकन करने प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 28 मई से हेलीकाप्टर के जरिए बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा 31 मई तक चलेगा।

संतोष पाण्डेय की रहेगी अहम भूमिका

ओम माथुर द्वारा बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में ली जा रही बैठकों में जमीन पर भाजपा के चेहरे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मानसिकता और चुनाव की रणनीति भविष्य में कैसी हो, इसका खाका तैयार किया जा रहा है। भाजपा के बस्तर संभाग प्रभारी एवं राजनांदगांव के सांसद संतोष पाण्डेय बस्तर संभाग का लगातार दौरा करते आ रहे हैं। वे ओम माथुर के दौरे में भी साथ रहे हैं। इस लिहाज से बस्तर संभाग की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी चयन में संतोष पाण्डेय की भी अहम भूमिका हो सकती है। अगर पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पार्टी नेतृत्व, संभाग प्रभारी संतोष पाण्डेय की सलाह लेते हैं, तो यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा ही साबित होगा और ओम माथुर को भी जिताऊ प्रत्याशी चयन में सहूलियत होगी।

बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर से पूरी सूचनाएं प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर और नई दिल्ली केंद्रीय भाजपा कार्यालय पहुंच रही हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार चेहरे पहचानने और पार्टी के स्थानीय नेताओं कार्यकर्त्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए ओम माथुर पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। वहीं एक खबर यह भी सामने आई है कि जगदलपुर सीट और अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र पर पार्टी विशेष रूप से फोकस कर रही है. क्योंकि इन दोनों सीटों पर ही आपसी टकराहट ज्यादा देखने को मिल रही है। जगदलपुर और अंतागढ़ क्षेत्र के नेताओं को निकट भविष्य में रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में तलब किया जा सकता है। ओम प्रकाश माथुर जहां बस्तर संभाग में प्रत्याशी चयन और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंथन कर रहे हैं, वहीं मैदानी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इसी रणनीति के तहत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के 15 वर्षीय भाजपा शासनकाल के वे सभी चेहरे और वर्तमान प्रदेश भाजपा संगठन से जुड़े रहे नेता अब लगभग मुखौटा बनाकर रख दिए गए हैं। पूरी रणनीति नई दिल्ली में तैयार हो रही है। अब तो यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनावों में सामूहिक सहमति के आधार पर प्रत्याशी मैदान पर उतारे जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा।

बड़े आंदोलन के जरिए होगा चुनावी शंखनाद

भाजपा का चुनावी शंखनाद एक बड़े आंदोलन के जरिए होगा। रणनीति के तहत जून माह में ही कोई बड़ा आंदोलन भाजपा कर सकती है। चुनाव की अंतिम रणनीति में भी मंथन कर आवश्यकता पड़ी तो बड़ा फेरबदल किया सकता है। अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेताओं को सामने लाकर पुराने और दागदार चेहरों को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर करने की रणनीति पर भी भाजपा में काम चल रहा है।

बस्तर संभाग में 10 जून के बाद मानसून आ जाता है और जब मानसून की विदाई होगी, तब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनावी नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे। सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभागों को माना जाता है। इन दोनों संभागों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बेहद असरकारी रणनीति बनाने में भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। 2018 के चुनावों में हुई करारी हार के कारणों पर भी पार्टी में मंथन किया जा रहा है। हार के पीछे के कारकों और नेताओं को भी लगभग किनारे कर दिया जाएगा।भाजपा हर हाल में इस बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सहित प्रदेश प्रभारी इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि पार्टी के कौन- कौन लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नजदीकी बनाए हुए हैं। आईबी सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई है।

बस्तर की सात सीटों पर उतारे जाएंगे नए चेहरे

बेदाग चेहरों की तलाश के लिए जबरदस्त आंतरिक मंथन चल रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अंदरखाने बारीकी से अध्ययन करके भविष्य में भाजपा संगठन के शिल्पी नेताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे सकता है। बस्तर संभाग की बारह में से सात विधानसभा सीटों पर नए और बेदाग चेहरों को मैदान पर उतारा जा सकता है। ये सीटें हैं जगदलपुर, बस्तर, अंतागढ़, नारायणपुर, कोंटा, भानुप्रतापपुर और केशकाल। इन सभी सीटों पर नए और निर्विवाद छवि वाले नेताओं पर भाजपा दांव लगा सकती है। जगदलपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर चुके मौजूदा विधायक रेखचंद जैन का सामना करने के लिए भाजपा किसी बौने प्रत्याशी को मैदान पर हरगिज नहीं उतारेगी। जगदलपुर विधानसभा सीट के लिए भाजपा दमदार और बेदाग एवं निर्विवाद छवि वाले व्यक्ति की तलाश के लिए जमकर मशक्कत कर रही है।

लोक लुभावन होगा घोषणा पत्र

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति की घोषणा जून में हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र नई दिल्ली में ही तैयार होगा। केंद्रीय भाजपा कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र तैयार होगा। घोषणा पत्र में किसानों, आदिवासियों, युवाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों के लिए प्रभावशाली और लोक लुभावन घोषणाएं शामिल की जा सकती हैं।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम ने बुधवार को कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से दो कट्टे और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी ओडिशा से हथियार लेकर यूपी जा रहा था। उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जीआरपी की टीम ने रुटीन चेकिंग के दौरान जोनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर सात पर एक युवक को संदिग्ध दशा में देखा। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो गोलमोल जवाब देने लगा। इस पर टीम उसे पकड़कर थाने ले आई। वहां तलाशी के दौरान युवक के पास मौजूद बैग से एक पैकेट बरामद हुआ। खालने पर पैकेट में दो कट्टे और कारतूस मिले। पूछताछ में पता चला कि, आरोपी मिथुन नायक उत्तरप्रदेश के औरैया का रहने वाला है। वह ओडिशा के संबलपुर से हथियार लेकर उत्तरप्रदेश जा रहा था। वह बिलासपुर से नर्मदा एक्सप्रेस में काशी जाने वाला था। हालांकि, ओडिशा में ये हथियार उसे किसने दिया उसकी जानकारी युवक नहीं दे रहा है।

विद्युत कनेक्शन में खराबी की वजह से कुछ समय अवरुद्ध थी पानी आपूर्ति

बालोद। ग्राम नारागांव एवं आश्रित ग्राम किनारगोंदी में पानी की समस्या होने की जानकारी मिलने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम में तत्काल निरीक्षण किया गया, निरीक्षण दौरान ग्राम के सरपंच श्रीमती प्रतिमा मंडावी ने प्रमाणित किया कि ग्राम में गंभीर पेयजल समस्या नहीं है। ग्रीष्म ऋतु के कारण उच्च जलागार देर से भरती है, पीएचई एवं ग्राम पंचायत पेयजल व्यवस्था पर लगातार ध्यान दे रही है। ग्राम में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो चुका है सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं एवं सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। सरपंच ने बताया कि विद्युत कनेक्शन में फाल्ट होने की वजह से कुछ समय के लिए जल प्रदाय

अवरुद्ध हुआ था। वर्तमान में निरंतर ग्रामीणों को पानी मिल रहा है।

प्रभारी उप अभियंता श्री चंद्रहास चंद्रवंशी ने बताया कि ग्राम की कुल जनसंख्या 1806 है। ग्राम में विगत वर्ष पेयजल हेतु 80 के एल जलागार का निर्माण तथा सभी गलियों में पाइप लाइन बिछाई गई है जल जीवन मिशन अंतर्गत 152 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया है वर्तमान में कुल 380 घरों में घरेलू नल कनेक्शन हो चुके हैं पेयजल हेतु 7 नग हैंडपंप जिसमें 6 नग चालू एवं एक नग जल स्तर गिरने के कारण बंद है साथ ही 5 नग सिंगल फेज पावर पंप स्थापित है जिसमें 4 चालू एक बंद है। भूजल पुनर्भरण के लिए लगातार आई एस ए के माध्यम से ग्रामीणों को सोख्ता गड्ढा एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि भूमिगत जल का रिचार्ज होते रहे भविष्य में सूखे की समस्या ना हो, साथ ही ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए घरों के किचन गार्डन में कोचई एवं केले का पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा। वर्तमान में जल प्रदाय संबंधित कोई भी समस्या गांव में नहीं है।

गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया औपचारिक निरीक्षण

दुर्ग। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के दुर्ग विकासखंड में विभिन्न गांवों का दौरा किया! जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपुजन के कार्यक्रमों में शामिल हुए।

इस कार्यक्रम के मुख्यअतिथि प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू थे, अध्यक्षता अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग पुष्पा भुनेश्वर यादव, विशेष अतिथि उपाध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल केशव बंटी हरमुख, अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग देवेंद्र देशमुख, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी जितेन्द्र साहू, जनपद उपाध्यक्ष झमीत गायकवाड़, कृषि सभापति योगिता चंद्राकर, प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष कृष्णा देवांगन, जेल संदर्शक भरत साहू ,जनपद सदस्य भुनेश्वरी ठाकुर, सरपंच ग्राम मोहलई खेमीन निषाद, सरपंच कोटनी मनोज साहू , सरपंच पिपरछेड़ी बाल किशन ठाकुर, सरपंच महमरा , जनपद सदस्य ज्ञानेश्वर मिश्रा सहित राजीव युवा मितान के सदस्य गण कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर गृह मंत्री ने ग्रामीणों से समस्याएं पूछीं और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर यह देखना है कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है और आपके गांव के विकास के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। ग्राम मोहलई में लगभग 30 लाख 20 हजार की राशि का लोकार्पण किया गया। जिसमें सी सी रोड़ निर्माण 2.60, शीतला घाट में निर्मला घाट निर्माण, 2.60,महिला घाट में सेट निर्माण 5 लाख, सीसी रोड़ निर्माण 5 लाख, बाल उद्यान निर्माण लोकार्पण,5 लाख सामुदायिक भवन सेन समाज 6लाख , आंगनबाड़ी संधारण कार्य 1.50 लाख, प्राथमिक शाला संधारण कार्य 2.50 लाख रूपये। इसी तरह ग्राम कोटनी में राम मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सामाजिक भवन का लगभग 10 लाख की राशि से भूमिपूजन किया गया। ग्राम पिपरछेड़ी में 19.96 लाख की राशि से बने चेक डेम का लोकार्पण साथ ही 6 लाख की लागत राशि से समुदायिक भवन का भूमिपूजन किया गया।

कुरूद विकासखण्ड की चार ग्राम पंचायतों में होगा सरपंच पद के लिए निर्वाचन

■ **रिक्त 14 पदों पर भी होगा पंचों चुनाव, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया आदेश जारी**

धमतरी। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पदों के लिए उप निर्वाचन किया जाना है इसके लिए आदर्श आचरण संहिता के परिपालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि जिले के कुरूद विकासखण्ड की तीन पंचायत चर्रा, चरमुड़िया तथा नवागांव उ. में सरपंच पद का आम निर्वाचन, ग्राम पंचायत सिलघट में सरपंच का उप निर्वाचन तथा चारों विकासखण्डों में कुल 14 पंचों के रिक्त पदों के विरूद्ध का चुनाव सम्पन्न कराया जाना है। इसके लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं।

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावी :- स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 के तहत जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि आम एवं उप निर्वाचन से संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में, जहां निर्वाचन होना है, वहां सम्पत्ति विरूपण नियम प्रभावशील हो गया है। तदनुसार उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

पूर्वानुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी :- त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की चारों जनपद पंचायतों के अधीन आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि उक्त निर्वाचन को दृष्टिगत करते हुए जिले में पदस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को उनकी पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे, न ही वे मुख्यालय छोड़ेंगे। इसके अलावा अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन संबंधी आदेशों/पत्रों को प्राप्त करने के लिए कार्यालयों को खुला रखने हेतु आदेशित किया गया है। रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए :- त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 के तहत जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा: मुख्यमंत्री

■ **1.05 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 32.35 करोड़ की राशि का किया ऑनलाईन अंतरण**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वेकेंसी निकाल रहे हैं इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग भर है, जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में

बेरोजगारी भत्ता योजना के एक लाख 5 हजार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हजार रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। इन हितग्राहियों में 66 हजार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रूपए, 24 हजार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोजगारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हजार रूपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार 15 हजार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई। बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई है।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव तकनीकी शिक्षा श्री टोपेश्वर वर्मा, सचिव कौशल विकास श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते की प्रथम किश्त के वितरण के समय पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे, आज हमने अपना वादा निभाया है। आज विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते है, तो कुछ लोग खेती-किसानी, तो कुछ लोग छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं। सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती। इन परिवारों के युवाओं को लगता है कि माता-पिता ने हमें लिखा-पढ़ा दिया लेकिन हम माता-पिता पर आश्रित हैं। ऐसे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलने वाली 2500 रूपए की राशि उनके लिए बड़ा सहारा है। इस राशि से प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताब खरीदने आदि कार्यों में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने व्यापम, पीएससी की परीक्षाओं में युवाओं की परीक्षा फीस माफ कर दी हैं। इससे इन परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार हो सकें। रीपा में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अच्छे वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही जनता से किए वादों को पूरा करने में हम सफल रहे हैं।

30 दिनों तक पूरी भाजपा उतरेगी मैदान में

2 केंद्रीय मंत्री, सांसद आएंगे, नए चेहरों को अभियान का जिम्मा, युवा-बुजुर्ग-व्यापारी सबको साधेगी

रायपुर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के शानदार 9 वर्ष पूरे किए हैं। ये नौ साल वास्तव में भारत के लिए युगपरिवर्तनकारी रहे हैं। इस कालखंड में देश ने जिन ऊँचाइयों को छूआ है, वह निस्संदेह ऐतिहासिक हैं।

बीते 9 वर्ष वास्तव में भारत के नवनिर्माण के, गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 9 सालों में भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव की यात्रा की है। भारत ने बीते 9 साल में एक पार्टी के अपना परिवार अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ, सबका विकास की कहानी लिखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर विकासवाद की राजनीति प्रतिष्ठित की है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को एक महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पार्टी ने 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' के मोदी जी के मंत्र को जन-जन तक पहुचाने की योजना बनायी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 31 मई से 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। 31 मई को राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एक महारैली करके इस महासंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। अगले एक महीने में देश भर में इस तरह की 51 महारैली आयोजित की जायेगी।

23 जून को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्य तिथि के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी डिजिटल रैली के माध्यम से 10 लाख बूथों पर समर्थकों, समाज में काम करने वाले लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद एवं संपर्क करेंगे। 30 दिनों के इस महा जनसंपर्क के अंतर्गत पूरे देश भर में 500 से अधिक सभाएं और 600 से अधिक प्रेस वार्ता आयोजित होंगे। इस दौरान 500 से अधिक लोकसभा और 4,000 से अधिक विधानसभों में 5 लाख से अधिक विशिष्ट परिवारों और हर लोक सभा में 1,000 विशिष्ट परिवारों से संपर्क साधा जाएगा।

भाजपा ने 543 लोक सभाओं को 144 क्लस्टरों में बांटा है। हर क्लस्टर में तीन से चार लोक सभा को शामिल किया गया है। हर क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता 8 दिन गुजारेंगे। पार्टी नेताओं और एवं कार्यकर्ताओं की दो टोलियां बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रियों एवं पार्टी पदाधिकारियों जैसे 288 बड़े नेता इस टोली में रहेंगे। ये 288 नेता हर विधानसभा में एक हजार मुख्य परिवारों से मिलेंगे, उन्हें श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट देंगे और उनसे समर्थन भी मांगेंगे।

पार्टी ने नौ वर्ष की उपलब्धियों को लेकर एक वेबसाइट 94earsofseva.bjp.org भी लॉन्च की है। भाजपा ने जन संपर्क एवं जनता से समर्थन के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर 9090902024 भी लॉन्च किया है। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण का मंत्र जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकास यात्रा के यही समय है, सही समय है और रुके नहीं, आगे बढ़े के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महासंपर्क अभियान के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व सह संयोजक श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल समिति के सदस्य अमरजीत छाबड़ा शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में इतने कार्यक्रम होंगे

- 30 मई 30 जून के मध्य संपर्क से समर्थन का कायक्रम जिसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विशिष्ट परिवारों से संपर्क किया जायेगा जिसमें शहीद परिवार, 1. प्रमुख खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति तथा समाज में प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क होगा। छत्तीसगढ़ इस सभी अभियान के प्रभारी श्री सौरभ सिंह, विधायक तथा श्री जगदीश रोहरा हैं।
- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक आमसभा सम्पन्न होगी जिसमें लोकसभा के पार्टी के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश स्तर पर राजेश मुणत जी होगें।
- प्रत्येक लोकसभा में मीडिया संवाद एवं प्रेस वार्ता के प्रभारी श्री अमित चिमनानी होंगे।
- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव और श्री अमरजीत छाबड़ा होगें।
- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में शोसल मीडिया इन्फ्लुएंशर मीट होगी जिसके प्रभारी श्री प्रशांत सिंह ठाकुर होंगे।
- प्रत्येक लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होगा प्रभारी श्री चंद सुंदरानी तथा श्री लाभचंद बाफना जी होगें।
- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में 卐विकास तीर्थ卐 कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय नेताओं को भाजपा सरकार में हुए प्रमुख विकास कार्यों को दिखाने ले जाया जावेगा इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री अनुराग सिंह देव तथा श्री किशोर राय जी होगें।

बाबू भैया की कलम से

शंकराचार्य ने बताया समाधान शराबबंदी के लिए पीना छोड़ दो

छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शराबबंदी का वायदा गले की फांस बना हुआ है।कहा जाता है कि वह राजा लोकप्रियता हासिल करता है जो जनता की दैनंदिनी दिनचर्या में कम से कम हस्तक्षेप करता है।जीवन को अपने ढंग से जीने की आजादी प्रदान करता है।प्रजातंत्र की मूल मंशा भी यही मानी गई है। इतिहास में दफन अनेक राजतांत्रिक राजा-महाराजाओं व बादशाहों के किस्से इस मामले में दर्ज हैं। जिन्होंने जनता के जीवन में उनकी इच्छा व उनकी धार्मिक आस्थाओं में चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उनका हश्र क्या हुआ।चाहे वो औरंगजेब, मो.तुगलक, चंगेज खान, सिकन्दर से लेकर हिटलर, मुसोलिनी व कोई अन्य हों या अंग्रेजी शासनकाल का काला साम्राज्य हो। 1947 में आजादी के बाद भारतवर्ष में प्रजातंत्र को भारत की जनता ने अपनाया।लगा अब इन सबसे हट कर कुछ अलग ही आने लगा है।आया भी पर जैसे जैसे हम आजादी के वर्षों को भोगते हुए अपने प्रजातांत्रिक शासकों के साथ आगे बढ़े तो सत्ता(तख्ते-ताऊस) का नशा चढ़ना शुरू हुआ।बिना सुरक्षा के जनता के बीच बिंदास विचरण करने वाले नेता अपने कर्मों के कारण अब 20-20 कमांडो के बीच अपनी सुरक्षा के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं।कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा तो प्रजातंत्र में राजाओं की तरह जनता पर अपनी मंशा थोपने का काम वोट पाने के चक्कर में शुरू कर रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी जिसे कहा जा रहा है वो राजनेताओं के घर के पैसे से नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे, उन्हें मदद के रूप में जनहित में लौटाने की प्रक्रिया मानी जानी चाहिए।यह जरूर कि मदद जरूरत मंदों को ही मिले यह तय होना चाहिए।कानून बनाने की शक्तियां होने के कारण सरकारें अब बंदिशों के सहारे भी वोट लेने की सोचने लगी है।जनता को सरकारों के बंदिशों के निर्णयों से अपनी प्रजातांत्रिक आजादी घुटती सी नजर आने लगी है। कभी कभी तो ऐसा भी सोचने लगी है कि क्या हम सच में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं , या यह सिर्फ अहसास मात्र है ? इतनी बंदिशें इतने अवरोध और ऊपर से हर चीज मंहगाई के मार से ग्रस्त है। देश की जनता सोचती है कि अब आखिर विकल्प है क्या ? प.जवाहरलाल नेहरू से ,लाल बहादुर शास्त्री,गुलजारीलाल नंदा (दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री) इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह,राजीव गांधी,विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर,पी.व्ही.नरसिम्हाराव,अटल बिहारी बाजपेयी,एच.डी.देवेगौड़ा , इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, और अब नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चल रहा यह महान देश भारतवर्ष, कभी भी महंगाई से निजात नहीं पा सका, ना गरीबी से ऊपर ही उठ पाया। बल्कि इस नए दौर में तो महंगाई के समर्थन करने वाले अंध भक्त भी देखने को मिल रहे हैं , जो कभी नहीं थे। यह जरूर इस देश ने देखा कि अनेक प्रधानमंत्रियों ने अपना नाम पैदा करने करोड़ो का जनधन लुटाया। आज भी लुटा रहे हैं, लेकिन अपने कोष से धन के दुरुपयोग को जनता रोक नहीं पाती। बंदिशों की कितनी बात की जाए , कितनी नहीं? कौन दोषी-कौन नहीं? इसी पचड़े में देश की जनता को कोई और दूसरा विचार आ ही नहीं पाता। किसी एक घटना को जेहन में दबा देने के लिए अन्य घटनाओं की इतनी परतें एक के ऊपर एक ऐसे जमा दी जाती हैं कि मूल समस्या गहरे दफन हो जाती हैं। जनता के लिए बस एक ही शब्द कहने को बच जाता है। बस "भारत भाग्य विधाता" कहा जाए। यानी भारत की जनता का भाग्य विधाता के ही हाथ है, जो इसे चला रहें हैं। महंगाई,पेट्रोल के दाम,अनाज व तेल के दाम अनेक घटनाएं जनता को याद ना आये। उसके जेहन में सिर्फ अनेक दूसरे-दूसरे प्रश्न उठते रहें ,और वो इसमें ही उलझता रहे। मूल समस्या से उसका ध्यान बंटा रहे। इसके रास्ते सरकारों के नुमाइंदे आसानी से निकाल लेते हैं। देश में यही परिदृश्य लंबे समय से दिखाई दे रहा है। कोई कुछ कर सके, यह स्थिति भी नही है। सरकारें यह क्यों नहीं सोचती कि इसी जनता के दिये मतों से ही वे सरकार में हैं। जनता के जीवन के सफर में कम से कम बाधा व हस्तक्षेप रहे, इसका ख्याल क्यों नहीं रखतीं? जैसे ही सरकारें बन जाती हैं, बंदिशों का दौर शुरू हो जाता है। अरे भाई जनता को अपनी भलाई स्वयं निर्धारित करने दीजिए। देश की दो तीन सरकारों ने शराब बंदी की, क्या परिणाम हुआ? जाने समझे बगैर क्यों छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को वायदे में शामिल किया गया। यह समझ कोई नहीं पाया। अब जाकर सरकार को इसका हर पक्ष समझ में आ रहा है। दिनों दिन बयान बदल रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य सब जानते हैं ,शराबबंदी का सच क्या है। इस आदिवासी बाहुल्य राज्य में यह झटके में करना असंभव ही नहीं,नामुमकिन है। सच वो है जो कल ज्योतिष्पीठाधीश्वर शकराचार्य महाराज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि शराबबंदी के लिए कानून बनने की बाट क्यों जोह रहे हैं? उसका सीधा सा हल है कि जो शराबबंदी चाहते हैं वे शराब पीना स्वयं से ही छोड़ दें। कानून नहीं बना रहे , इसलिए सरकार से नाराज होने से हल नहीं है। खुद शराब पीना छोड़ दें तत्काल समाधान हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने सच कह दिया मानना ना मानना आपका काम है। यानी आप शराबबंदी चाहते हैं तो तत्काल छोड़ दें। कानून से नहीं यह समस्या दृढ़ इच्छाशक्ति से सुलझेगी। शंकराचार्य जी की बात आप समझे कि नहीं? ना समझे वो.........?

जल संसाधन विभाग के प्रभारी एसडीओ धीवर निलंबित

रायपुर। जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था। निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

पॉवर कंपनी में अधिकारियों को दी गई विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में कार्यरत उच्च अधिकारियों को सेवानिवृत्त पश्चात् भावभीनी विदाई दी गई। जनरेशन कंपनी से सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक अरूण कुमार वर्मा एवं मुख्य अभियंता विमल मिश्रा को तथा डिस्टीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक नरोत्तम लाल साहू को कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवाभवन में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी मनोज खरे, जनरेशन कंपनी के एमडी एस.के.कटियार, डायरेक्टर के.एस.रामाकृष्णा ने उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इसके अलावा ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (संचार एवं टेलीमेटरी भिलाई) केके भौरासे को भी प्रबंध निदेशक श्री खरे ने सेवाभवन में प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवाओं को प्रदेश के विद्युत विकास के लिए महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए उनके द्वारा विद्युत मंडल एवं कंपनी में किये गये योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त ईडी श्री वर्मा, जीएम श्री साहू एवं सीई मिश्रा ने अपने कार्य अनुभव बताते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया। तथा सेवायात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों में ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सहायक प्रबंधक श्री शीतल साहू एवं अनुभाग अधिकारी श्री अमित मेहता को तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में निज सहायक श्री वाई सूर्यप्पा राव, कार्यालय सहायक श्रेणी 01 श्री तुलसी प्रसाद तिवारी एवं जनरेशन कंपनी के वित्त संकाय में सहायक प्रबंधक श्री एचएल घिरही को भी भावभीनी विदाई दी गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भूपेश- सिंहदेव की लड़ाई में जनता की जान पर बन आई: बृजमोहन

रायपुर। बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा की गई 1 जून से राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा को पलीता लग जाने का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसकी सरकार की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सतह पर आ गई है कि इसके लिए वे जनता के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। साथ ही दवाइयां और जांच भी निशुल्क होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में भूपेश बघेल की संवेदनहीन सरकार ने आपसी कलह में छत्तीसगढ़ की जनता का जीवन संकट में डाल दिया है। जनसेवा की बजाय भूपेश बघेल सरकार केवल घोटाले कर रही है और आपसी जंग में जनता को ही दांव पर लगा दिया गया है। सिर्फ वही दावा करते हैं जो उनकी सरकार कर ही नहीं सकती। उन्हें पता है कि जब बजट में मुफ्त इलाज, मुफ्त परीक्षण, मुफ्त दवा के लिए राशि ही नहीं है तो उनकी यह योजना कैसे सफल होगी। कुल मिलाकर भूपेश बघेल और टीएस की नूरा कुश्ती में जनता पिस रही है। जनता से एक और लुभावने वादे करके उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है।

बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त भूपेश है तो भरोसा हैः कांग्रेस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज 1.05 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की 32.35 करोड़ की दूसरी किश्त जारी करने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार युवाओं के हितों में निर्णय ले रहे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार युवाओं के रोजगार को ध्यान में रख कर योजनायें बना रहे, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर आधा प्रतिशत से भी कम है तथा आज छत्तीसगढ़ सरकार के हर विभाग में युवाओं के लिये भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिये काम कर रहे है यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर आधा प्रतिशत से कम है। बेरोजगारी भत्ता इसीलिये दिया जा रहा है ताकि युवा आगे के लिये तैयारी कर सके, आर्थिक बोझ न पड़े। कांग्रेस रोजगार देने में विश्वास रखती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 4 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, और सरकारी नोकरी देने में सफलता हासिल की है। और रोजगार मिशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय प्रदेश की युवाओं के साथ न्याय हैं। बेरोजगारी भत्ता के दौरान प्रदेश के युवाओं को रोजगार संबंधित ट्रेनिंग दी जाएंगे।

पटवारी ही नहीं 35 लाख कृषक भी प्रभावित है इस हड़ताल से

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बुधवार को पटवारियों की हड़ताल को समर्थन देने नया रायपुर के धरनास्थल पर पहुँचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक शिवरतन शर्मा तथा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा भी थीं।इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि पिछले लगभग पखवाड़ेभर से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार आंदोलनरत पटवारियों की न तो मांगें पूरी कर रही है और न ही उनसे चर्चा कर रही है। प्रदेश में राजस्व संबंधी कार्य प्रदेश सरकार की हठवादिता के कारण ठप पड़े हैं। प्रदेश सरकार को संवेदनशील होकर पटवारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रदेशभर में आंदोलनरत 5 हजार पटवारी शासकीय मशीनरी के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और उनकी अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है। श्री साव ने पटवारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए इस बात पर अफ़सोस जताया कि बजट में दो बार प्रावधान करने के बाद भी प्रदेश सरकार ने पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता नहीं दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कार्यसंपादन के लिए पटवारियों को आवश्यक सामग्री व संसाधन मुहैया कराना प्रदेश सरकार की ज़िम्मेदारी है। श्री साव ने कहा कि भाजपा पटवारियों की मांगों को हर मंच पर उठाएगी।

कमल पर लड़ने का निर्णय लेकर भाजपा ने माना छत्तीसगढ़ में उसके पास नेतृत्व नहीं

रायपुर। भाजपा के द्वारा यह कहा जाना कि आने वाले चुनाव में कमल छाप को आगे करके चुनाव लड़ेगी कोई चेहरा सामने नहीं होगा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कमल पर लड़ने का निर्णय लेकर भाजपा ने मान लिया छत्तीसगढ़ में उसके पास नेतृत्व नहीं। भाजपा इसके पहले बयान देती थी कि वह छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटका चुनाव में बुरी तरह हार के बाद भाजपा मोदी के चेहरे को भी आगे करने से डर रही है। कर्नाटका में भाजपा ने मोदी को आगे कर चुनाव लड़ा था उसे समझ आ गया कि मोदी का चेहरा भी अब चुनाव जिताऊ नहीं रहा इसीलिये छत्तीसगढ़ में वे स्थानीय नेताओं के साथ मोदी के चेहरे से भी किनारा करने का निर्णय लिया गया है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं पर से जनता का भरोसा उठ ही गया था, अब उनके आलाकमान को भी भरोसा नहीं है। स्वयं रमन सिंह के नेतृत्व को जनता 2018 में नकार दिया था। रमन मंत्रिमंडल के सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के दाग लगे है। यही कारण है कि किसी को चेहरा बनाने का साहस नहीं दिखा पा रही।

मोदी सरकार के 9 साल जनता बदहाल : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा के जनसंपर्क अभियान को राजनैतिक नौटंकी करार देते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल जनता की बदहाली का रहा। मोदी राज में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से जितनी परेशान है उतना कभी नहीं रही। भाजपा सरकार मोदी सरकार की कौन सी उपलब्धि को जनता के बीच लेकर जाने की बात कर रही है। कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचायेगी। जनता मोदी सरकार की विफलता को खुद भोग रही है। मोदी सरकार 9 साल स्वतंत्र भारत के काला अध्याय रहे है। इन आठ सालों में देश की प्रगति रूक गयी। देश की बेरोजगारी दर घट गयी, लोगों की नौकरियां चली गयी, 2.5 करोड़ लोगों के हाथों से कमाई के साधन छिन गये। 45 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार पाने इच्छा समाप्त हो चुकी है। आजादी के बाद पहली बार देश की उत्पादकता इतने निचली स्तर पर है, बेरोजगारी दर आसमान छू रही है। महंगाई बेलगाम है। नोटबंदी, जीएसटी जैसे अदूरदर्शी निर्णयों ने देश के उद्योग धंधे अर्थ तंत्र की कमर को तोड़कर रख दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल भाजपा के झूठे वायदों और जनता को मुंह चिढ़ाने वाले साबित हुये। जनता से हर के खाते में 15 लाख देने के वायदों को जुमला बता दिया।

योजनाओं से आ रहा सकारात्मक बदलावः मंत्री गुरू

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार आज दुर्ग जिले के करंजा भिलाई में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकर्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले और विकास कार्यों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री गुरू रूद्रकुमार से स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही और बोर खनन, शेड निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की।इस अवसर पर मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने एक करोड़ 16 लाख रूपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। जिसके अंतर्गत किसान कुटीर भवन, बाजार चौक सीमेंटीकरण कार्य, चबूतरा शेड निर्माण, हाई स्कूल में वाचनालय भवन, सांस्कृतिक भवन चौक सीमेंटीकरण, शीतला तालाब में शेड निर्माण, पुलिया निर्माण, रोड का सीमेंटीकरण इत्यादि कार्य शामिल हैं।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा भुनेश्वर यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री राजेन्द्र साहू, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी बोर्ड श्री अश्वनी साहू, सभापति जनपद पंचायत श्रीमती हिरामणी देशमुख सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

मानविकी विषयों पर गंभीर शोध वर्तमान समय की मांगः शुक्ला

■ **अग्रसेन महाविद्यालय में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन**

रायपुर। अग्रसेन महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय तथा आई.क्यू.ए.सी द्वारा अदिति प्रकाशन रायपुर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित तीन-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज सम्पन्न हो गई.. गुणवत्तापूर्ण शोध-पत्र का लेखन एवं प्रकाशन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के समापन समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सच्चिदानंद शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में ग्रन्थपाल डॉ सुपर्ण सेनगुप्ता उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि शोध में तीन आई, (खोज, नवाचार और अनुसन्धान) के मॉडल का उपयोग होना चाहिए. साथ ही मानविकी विषयों पर गंभीर शोध इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. आज के तकनीकी सत्र में डॉ. प्रफुल्ल कुमार वैद्य ने रिसर्च जर्नल के अंत में निष्कर्ष, सन्दर्भ तथा बिब्लियोग्राफी लिखने सम्बन्धी तकनीकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सन्दर्भ और बिब्लियोग्राफी को लेकर कई बार शोध लेखन करने वालों को भी भ्रम का सामना करना पड़ता है. इस विषय में हमें सही और तथ्यपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.